04 - एक देश एक चुनाव : 'संघीय ढांचे पर अतिक्रमण' कैसे ?

05 - बुजुर्गों के प्रति सम्मान का अभाव और बढ़ती मुश्किलें

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2024

06 - बैतूल जिले के कई स्थानों पर भूकंप के झटके

07- प्राइवेट स्कूल में बच्ची से रेप, पेरेंट्स का हंगामा....

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-34 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्याः म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

परीक्षाओं में असफल हुए पुरुष
अक्सर प्रेम में भी असफल हो जाते हैं
विवाह की पहली रस्म
पुरुष की आय पूछना होती है
दूसरी पुरुष की आयु
तीसरी पुरुष का आवास
और चौथी, पुरुष का गोत्र
परीक्षाओं में असफल पुरुष
अक्सर गँवा बैठते हैं
आय, आयु, और आवास
परीक्षाएँ देते-देते
असफल पुरुष का
कोई गोत्र नहीं होता
न ही कोई प्रेम कहानी
असफलता उसका अस्तित्व होती है
परीक्षा उसका जीवन
शर्म, उसके हिस्से आये ढाई अक्षर।

- अभिषेक शुक्ला

प्रसंगवश

हरियाणा : कांग्रेस की गलतियों से दलितों को लुभाने में जुटी बीजेपी

शंकर अर्निमेष

हरियाणा के कलानौर में राज्य के दलित समुदाय के तीन किसान दोपहर की धूप में अपने खेतों के पास ताश के पत्तों पलट रहे हैं। उनका खेत पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ रोहतक से 15 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। राज्य में पांच अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्तारूढ़ भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। वहीं कलानौर के किसान में नाराज़गी है।

अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित 90-सदस्यीय विधानसभा की 17 सीटों में से एक कलानौर निर्वाचन क्षेत्र के दलित किसान वेदपाल ने कहा, 'कांग्रेस ने दलितों को प्लॉट देने का वादा किया है और पेंशन दोगुनी करने की घोषणा की है। हमारी फसल को एमएसपी नहीं मिल रही है। हम भाजपा को वोट क्यों दें? उन्होंने मुफ्त राशन देने के अलावा गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। हम इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे।'

वेदपाल के दोस्त कृष्ण, जो खुद भी किसान हैं, ने सहमति में सिर हिलाया। भाजपा के खिलाफ दलितों में नाराज़गी भले ही बढ़ रही हो, लेकिन भाजपा बिना लड़े हार नहीं मानेगी। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, इसके लिए प्रमुख दलित नेता कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचार से दूर रहने के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और दलितों के खिलाफ हिंसा के दशकों पुराने मामलों को उठाया जा रहा है। विश्लेषकों का सुझाव है कि एक दशक की सत्ता विरोधी लहर, किसानों के जारी विरोध प्रदर्शन, बढ़ती बेरोज़गारी, अग्निवीर का विरोध और कांग्रेस के संवैधानिक परिवर्तन अभियान ने सामूहिक रूप से पार्टी के लिए दलित समर्थन को मजबूत किया है। कलानौर में भाजपा ने तीन बार की मौजूदा कांग्रेस विधायक शकुंतला खटक के खिलाफ पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान मेयर रहीं रेणु डबाला को मैदान में उतारा है। खटक हुड्डा के समर्थन पर भरोसा कर रही हैं, जबकि डबाला को उम्मीद है कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर उन्हें अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने में मदद करेगी।

लगभग 150 किलोमीटर दूर, अंबाला जिले में एक और एससी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र मुलाना के भाजपा गढ़ में, माहौल अलग नहीं है। मुलाना के खानपुर गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान पर तीन किसान चाय की चुस्की लेते हुए बैठे हैं। वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बलजिंदर ने कहा, 'हमने भाजपा सरकार के 10 साल देखे हैं। राशन के अलावा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के विरोध के दौरान बॉर्डर बंद रखे जो कि आज भी बंद है। सरकार का कहना है कि हम किसान नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। भाजपा का दावा है कि उसने 24 फसलों पर एमएसपी दिया है, लेकिन सरकार मंडी से दो से अधिक फसलों की खरीद नहीं कर रही है।'

इन तीनों ने 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया था, लेकिन इस साल उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया और विधानसभा चुनाव में भी उसी पार्टी को वोट देंगे। अंबाला को भाजपा का गढ़ माना जाता था, जहां हरियाणा में पार्टी का दलित चेहरा रतन लाल कटारिया 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रतिनिधित्व करते थे।

2023 में उनकी मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी, बंतो कटारिया ने इस साल के संसदीय चुनावों में एससी-आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ा। हालांकि, उनके पक्ष में सहानुभूति लहर के बावजूद वे कांग्रेस से हार गईं। मुलाना में भाजपा ने संतोष चौहान सरवन को मैदान में उतारा है, जो पहली बार 1991 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे और फिर 2014 में भाजपा के टिकट पर फिर से चुने गए।

उनकी प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के लोकसभा सांसद वरुण चौधरी की पत्नी पूजा चौधरी हैं। वरुण 2019 के विधानसभा चुनावों में मुलाना से चुने गए थे।

हरियाणा की राजनीति को आमतौर पर जाट और नॉन-जाट जातियों के एकजुट होने के चश्मे से देखा जाता है। हरियाणा में प्रमुख जाति समूह जाट, जो राज्य की आबादी का 25 प्रतिशत है, कांग्रेस, खासकर हुड्डा गुट के समर्थन की रीढ़ है। दूसरी ओर, 33 प्रतिशत आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) भाजपा का समर्थन करते हैं।

लेकिन इस चुनाव में निर्णायक कारकों में से एक दलित आबादी है, जो राज्य की आबादी का 21 प्रतिशत है। यह भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जाटों और दलितों के बीच एकता के कारण कांग्रेस का समर्थन बढ़ा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को पांच लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ।

हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा विपक्षी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की खबरों का उपयोग करके कांग्रेस से इस महत्वपूर्ण वोट आधार को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है, खासकर हुड्डा और शैलजा के बीच (प्रमुख दलित व्यक्ति जो कि सीट वितरण से असंतुष्ट बताई जा रही हैं)।

कांग्रेस में असंतोष की सुगबुगाहट तब और बढ़ गई जब शैलजा 18 सितंबर को राज्य चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र को जारी करने के दौरान समारोह में शामिल नहीं हुईं और अभियान से दूर रहीं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में एक रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला किया और दलितों को कांग्रेस से सावधान रहने के लिए कहा।

गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हफ्ते एक रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस द्वारा नामित उम्मीदवार जस्सी पेटवार के समर्थक, जिन्हें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का करीबी माना जाता है, ने शैलजा के बारे में जातिवादी टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा ने सोशल मीडिया पर शैलजा के अपमान की कहानी को आगे बढ़ाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को इसमें बीच-बचाव करते हुए कड़ी निंदा जारी करनी पड़ी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घरौंडा में एक रैली में शैलजा को भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। पूर्व सीएम ने कहा, 'कांग्रेस में बहुत अंदरूनी कलह है। हमारी बहन शैलजा घर बैठी हैं। उनसे नाराज़ कई लोगों को भाजपा ने संग मिलाया है। हम फिर से उन्हें भी संग लाने के लिए तैयार हैं और अगर वे आती हैं, तो हम उन्हें शामिल करने के लिए तैयार हैं।' बाद में शैलजा ने खट्टर के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पार्टी में असंतोष की खबरों को खारिज कर दिया।

चुनावों से पहले दलितों का दिल जीतने की कोशिश में जुटी भाजपा के शाह ने लोगों को हुड्डा के कार्यकाल के दौरान 2005 में गोहाना और 2010 में मिर्चपुर में दलितों पर हुए हमलों की भी याद दिलाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले हमलों को उछालने से मतदाता प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि हिंसा की यादें केवल पुरानी पीढ़ी के ज़ेहन में है, जबकि नई पीढ़ी को हमलों के बारे में बहुत कम जानकारी है।

ऐसा लगता है कि हरियाणा में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। मतदाता किसानों के अनसुलझे विरोध, अग्निवीर योजना के लागू होने और राज्य में फैली बेरोज़गारी से नाखुश हैं। खट्टर सरकार की परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) योजना को लेकर दलितों में नाराज़गी बढ़ रही है क्योंकि अधिकांश वंचित समूहों को पोर्टल पर डिटेल्स सही करने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। इस बीच, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए समर्थन मजबूत बना हुआ है, खासकर किसानों, जवानों और पहलवानों के बीच। हरियाणा में भाजपा के दलित समर्थन आधार अचानक नहीं घटा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन आधार 2019 में 51 प्रतिशत के मुकाबले 2024 में घटकर 24 प्रतिशत रह गया है। इस बीच, कांग्रेस में लगातार उछाल देखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक ने दलितों के 68 प्रतिशत वोट हासिल किए।

इस बार दो जाट पार्टियां - जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी (एएसपी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के साथ गठबंधन करके दलित वोट बैंक को सुरक्षित करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं।

अन्य आंकड़े भी भाजपा के लिए घटते समर्थन की ओर इशारा करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटें जीती थीं। 2024 में पार्टी ने दो आरक्षित सीटों, सिरसा और अंबाला सहित पांच सीटें खो दीं।

2019 के 15 से 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा की बढ़त घटकर चार रह गई। कांग्रेस ने अपनी बढ़त पिछली बार के दो से बढ़ाकर 11 कर ली। 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 2014 में 9 से घटकर सिर्फ पांच आरक्षित एससी सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने सात एससी सीटें और जेजेपी ने चार सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 20 प्रतिशत से ज़्यादा एससी आबादी वाले 47 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की बढ़त 2019 के 44 से घटकर 18 रह गई, जबकि कांग्रेस की बढ़त 2019 में सिर्फ दो सीटों से बढ़कर 25 हो गई।

लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने दलित और पिछड़े समुदायों को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू की। भाजपा वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी) का समर्थन हासिल करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। दलितों को दिए गए 17 टिकटों में से नौ डीएससी समूह से हैं।

सोमवार को हरियाणा भाजपा के संगठन महासचिव फणींद्र नाथ सरमा ने डीएससी समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए दलित महापंचायत के नेता और पंचायत के अध्यक्ष से मुलाकात की। इस दलित समूह ने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए पिछले हफ्ते जींद में महापंचायत की। हालांकि, भाजपा को दलित वोट खोने का खतरा बना हुआ है। भाजपा को उम्मीद है कि बसपा, इनेलो और जेजेपी का तीसरा मोर्चा कांग्रेस के दलित वोट बैंक को विभाजित करने में मदद कर सकता है। बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन करके हरियाणा में 30 से अधिक उम्मीदवार उतारे हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार-दरभंगा में कोसी पर बना बांध टूटा, 12 जिलों में बाढ़

8 प्रखंडों के 58 स्कूल 2 अक्टूबर तक बंद, एक लाख लोग प्रभावित

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा है। दरभंगा में सोमवार देर रात कोसी नदी का बांध टूट गया। इससे एक लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर और बगहा जिले में भी बागमती नदी के 6 तटबंध टूटे हैं।

प्रशासन ने पश्चिम चंपारण जिले में 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक बंद कर दिया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सुपौल और पश्चिमी चंपारण के इलाके में पड़ा है। अररिया में भी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया। अगले 24 घंटे में बाढ़ का दायरा बढ़ेगा। उधर, राजस्थान में झालावाड़, बारां, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई।

नेपाल में बाढ़-भूस्खलन- 170 लोगों की मौत, 300 से अधिक घर डूबे, 16 पुल टूटे

नेपाल में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां गुरुवार से लगातार पानी गिर रहा है। इसकी वजह से पूर्वी और मध्य नेपाल के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ भी आई है। अकेले काठमांडू घाटी में 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की वजह से 55 से ज्यादा लोग लापता हैं और 100 से अधिक घायल हुए है। साथ ही कम से कम 322 घर और 16 पुल अब तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

मिथुन चक्रवर्ती को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

नई दिल्ली (एजेंसी)। इस साल दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार (30 सितंबर) को यह घोषणा की। मिथुन दा को 8 अक्टूबर को 70वीं नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी में सम्मानित किया जाएगा। मिथुन करीब 5 दशक के करियर में बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओडिया और भोजपुरी की 350 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। पीएम मोदी समेत कई अभिनेताओं और नेताओं ने मिथुन दा का बधाई दी।

दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलने पर मिथुन दा ने कहा मैं निःशब्द हूं- सच कहूं तो इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार पाकर मैं निःशब्द हूं। न मैं रो पा रहा हूं न मैं मुस्कुरा पा रहा हूं। इतनी बड़ी चीज है।

मुख्यमंत्री यादव ने झारखण्ड के दुमका में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में कहा

झारखंड अनंत संभावनाओं का प्रदेश है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा इसे विकसित बनाएगी : डॉ. मोहन यादव

झारखंड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को झारखंड के दुमका में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब झारखंड प्रदेश बना रहे थे, तब कांग्रेस और सोरेन परिवार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। कहा था कि हमारी लाश पर झारखंड प्रदेश बनेगा। आज वही लोग वोट मां रहे हैं,

इन्हें वोट मांगने का अधिकार नहीं है। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जनजातीय नायक भगवान बिरसा मुंडा को आजादी के बाद कांग्रेस ने भुला दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद भगवान बिरसा के योगदान को भाजपा सरकार ने देश के गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। स्वर्गीय अटल जी ने झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए गठन किया था, लेकिन राज्य बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का सोरेन परिवार और कांग्रेस ने इस राज्य को लूटने का कार्य किया।

आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार आदिवासियों के नाम पर राजनीति करता है। सोरेन परिवार झूठ बोलकर, भोले-भाले आदिवासियों से वर्षों से वोट लेते रहे और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन आदिवासियों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब आदिवासी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति बना रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया। वे आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनने दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों को सम्मान देने के लिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति बनाया। झारखंड अनंत संभावनाओं का प्रदेश है। इसकी धरती के नीचे अपार खनिज संपदा छिपी हुई है। संभावनाओं के इस प्रदेश को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर लूटने का कार्य किया है। इस प्रदेश का गठन स्वर्गीय अटल जी ने विकसित बनाने के लिए किया था। अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस प्रदेश को विकसित बनाने के लिए कार्य कर रहे है।

म.प्र. के 35वें मुख्य सचिव होंगे अनुराग जैन

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे, म.प्र.पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एक्ट लागू कराने में रहा अहम रोल

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के नए मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। वे अगस्त 2025 तक इस पद पर रहेंगे। हालांकि नियुक्ति आदेश शाम तक जारी होने के आसार थे। अनुराग जैन 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। मौजूदा मुख्य सचिव वीरा राणा का सर्विस एक्सटेंशन 30 सितंबर को खत्म गया। जैन को मुख्य सचिव बनाने से किसी भी अफसर को सुपर सीड नहीं किया जाएगा।

उनकी नियुक्ति का आधार अनुभव और सीनियोरिटी है। हालांकि वे सीएम डॉ. मोहन यादव की पसंद भी हैं। अनुराग जैन को सीएस बनाने की चर्चा नौ महीने पहले भी हुई थी,

जब सीएम डॉ. मोहन यादव से दिल्ली स्थित एमपी भवन में उनकी मुलाकात हुई थी। माना जा रहा था कि वे जल्द ही एमपी लौट सकते हैं। अनुराग जैन को केंद्रीय प्रति नियुक्ति से वापस करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने डीओपीटी को पत्र भेजा है।

हालांकि आज सुबह सीएम हाउस में 1990 बैच के आईएएस डॉ. राजेश राजौरा को वहां मौजूद अफसरों ने बधाई भी दे दी थी। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में थे। उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आधे घंटे तक मुलाकात भी हुई। अनुराग जैन 30 मई 2020 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। पूर्व मुख्य सचिव रहे इकबाल सिंह बैंस के एक्सटेंशन के समय भी जैन के मुख्य सचिव बनने की चर्चा थी, लेकिन केंद्र ने उन्हें नहीं छोड़ा। बता दें, अनुराग जैन के साथ राजेश राजौरा, मोहम्मद सुलेमान और जेएन कंसोटिया के नाम भी मुख्य सचिव के लिए चर्चा में थे।

मोदी 3.0 में अहम मंत्रालय की कमान मिली थी

10 साल पहले पीएमओ में संयुक्त सचिव रहे अनुराग जैन को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में सबसे अहम मंत्रालय रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की कमान दी गई है। जैन मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बार सचिव रह चुके हैं। वे भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। जैन वित्त प्रबंधन के अच्छे जानकार माने जाते हैं।

यही वजह है कि 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद कमलनाथ सरकार ने उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन मई 2020 में वे फिर से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र चले गए। अनुराग जैन ने दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है। अनुराग जैन की मध्यप्रदेश में पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एक्ट को लागू कराने में अहम भूमिका रही है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में भी उनका अहम रोल रहा। सूत्रों की माने तो जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल से झारखंड के लिए रवाना हुए तब तक दिल्ली से किसी भी तरह कोई मैसेज नहीं पहुंचा था। इसलिए यह माना जा रहा था कि डॉ. राजेश राजौरा ही प्रदेश के अगले मुख्य सचिव बनाए जाएंगे। सीएम के रवाना होने के बाद दिल्ली से यह संदेश पहुंचा कि अनुराग जैन को मुख्य सचिव बनाया जाए।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 36.3 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 01 अक्टूबर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

संक्षिप्त समाचार

नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से गरमाई बिहार की सियासत

- क्या समय से पहले होंगे चुनाव? एक्शन मोड में सभी पार्टियां

पटना (एजेंसी)। विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हो रहे हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी बिहार में दिख रही है। हर दल इस तरह एक्टिव है, जैसे आमतौर पर चुनाव के दौरान होता है।

जेडीयू का कार्यकर्ता समागम- दूसरे दल अगर चुनाव की आहट का अनुमान लगा कर ऐसा कर रहे हों तो आश्चर्य नहीं, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू भी अगर सक्रिय है तो इसकी कोई न कोई वजह जरूर होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा कार्यकर्ता समागम 27 सितंबर से शुरू कर चुके हैं। उनकी तैयारी हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने की है। नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा का चयन शायद इसलिए किया है कि वे पार्टी के सुलझे हुए नेताओं में शुमार किए जा रहे हैं।

शाह बोले-खड़गे ने अपने नेताओं से ज्यादा घटिया बात कही

- कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू में कहा था, मोदी को पीएम पद से हटाए बिना मरने वाला नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मोदी पर दिए बयान पर निशाना साधा। शाह ने कहा- कांग्रेस अध्यक्ष अपने पार्टी नेताओं से ज्यादा शर्मनाक बयान देते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अनेक वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। दरअसल, कठुआ में एक रैली के दौरान 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई थी। बाद में लौटकर उन्होंने कहा था कि जब तक वे मोदी को हटाएंगे नहीं, जिंदा रहेंगे।

महबूबा बोलीं-

हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकी

- नसरल्लाह को शहीद बता चुकीं; विरोध हुआ तो कहा- भाजपा उनके संघर्ष को नहीं जानती

श्रीनगर (एजेंसी)। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर के बाद सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैंबर में बदल दिया है।

त्यौहारों में रहें सावधान

उंगली बराबर केले को जहर भरकर किया जा रहा बड़ा

60 रुपए दर्जन में हर घर पहुंच रहा कैंसर

नईदिल्ली (एजेंसी)। त्यौहारों का सीजन शुरु हो गया है। केला एक ऐसा फल है जिसके स्वास्थ्य को अनगिनत फायदे हैं। इसमें वो सभी जरूरी पोषक तत्व पाए हाते हैं, जो शरीर के बेहतर कामकाज के लिए चाहिए। केला केले पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन बी6, फास्फोरस जैसे विटामिन और मिनरल्स का भंडार होता है।

केला खाने से पाचन मजबूत करने, वजन घटाने, वजन बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने, ऊर्जा का लेवल बढ़ाने, दिल को स्वस्थ रखने और ब्लड शुगर कंट्रोल करने और कई फायदे मिलते हैं। लेकिन यह फायदे आपको तभी मिल सकते हैं, जब आप नेचुरल तरीके से पका केला खा रहे हों।

मगर क्या आप जानते हैं कि आप जो केला खा रहे हैं, वो खतरनाक केमिकल्स से पकाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि केले को समय से पहले तोड़कर उन्हें जबरदस्ती केमिकल्स से पाकर बाजार में बेचा जा रहा है। जाहिर है ऐसे में

मजबूरन आपके शरीर में जहर घोला जा रहा है।

कार्बाइड का क्या मतलब है?- कार्बाइड, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बाइड का केले और अन्य फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक ऐसा केमिकल है जिस पर भारत सहित कई देशों में बैन है। इसे स्वास्थ्य के लिए खतरा माना गया है। इससे पके फलों को खाने से कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है।

भारत में बैन है यह केमिकल- कैल्शियम कार्बाइड में आमतौर पर आर्सेनिक और फास्फोरस होते हैं। इन केमिकल्स के इस्तेमाल से सेहत को कई नुकसान हो सकते हैं। इन खतरों के कारण, खाद्य सुरक्षा और मानकों के विनियमन 2.3.5 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध (आरईएफ) लगा दिया गया है।

खत्म हो जाते हैं पोषक तत्व

कृत्रिम रूप से पके फलों में अक्सर प्राकृतिक रूप से पके फलों की तुलना में कम पोषण मूल्य होता है। उनमें शुगर और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य लाभ कम हो जाते हैं।

कार्बाइड से पके केले की पहचान कैसे करें

- कार्बाइड से पके केले अक्सर असमान रूप से पकते हैं। केले के कुछ हिस्से पीले हो सकते हैं जबकि अन्य हरे रह सकते हैं।
- कैल्शियम कार्बाइड से पके केले प्राकृतिक रूप से पके केले की तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं।
- कार्बाइड से पके केले की त्वचा अक्सर अधिक पीली दिखाई देती है और चमकदार दिखाई दे सकती है, लेकिन मांस कम पका हुआ या सख्त रहता है।
- प्राकृतिक रूप से पके केले को छूने पर मुलायम महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह अपना आकार बनाए रखता है। यदि केला पूरी तरह पीला होने पर भी बहुत सख्त है, तो यह रसायन से पकाया गया हो सकता है।
- प्राकृतिक रूप से पके केले में एक सुखद, मधुर खुशबू होती है। रसायन से पके केले में यह प्राकृतिक खुशबू नहीं होती।

विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का फैसला

गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देशी गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। सोमवार (30 सितंबर) को कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान हैं। इसलिए हमने इन्हें 'राज्य माता' का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हम गोशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन-पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने जा रहे हैं। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती थीं, इसलिए यह फैसला लिया गया है।

'31 अक्टूबर को नहीं, 1 नवंबर को दिवाली मनाना सही'

इंदौर में 150 से अधिक पंचांगकारों की सहमति से फैसला, वजह भी बताई

इंदौर (नप्र)। इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या फिर 1 नवंबर को? इसका जवाब ज्योतिष और विद्वत परिषद ने दे दिया है। इंदौर में हुई बैठक में इस बार दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाना तय किया गया है।

1 नवंबर को दीपावली मनाने को 90 प्रतिशत पंचांगकारों ने समर्थन किया है, उस पर सहमति दे दी गई है। इसके लिए सोमवार दोपहर में इंदौर के संस्कृत महाविद्यालय में विद्वानों और आचार्य की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया है।

विद्वान बोले- 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा- मध्यप्रदेश वैदिक और विद्वत परिषद के वैदिक आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया कि सोमवार को मध्यप्रदेश ज्योतिष और विद्वत परिषद की ओर से विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ। जिसमें विद्वानों ने अपने-अपने मत रखे। 90 प्रतिशत से अधिक विद्वानों ने ये मत रखा कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना शास्त्र सम्मत होगा। इस साल 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को, दोनों ही दिन अमावस्या तिथि प्रदोष काल में है। ऐसी स्थिति में धर्म शास्त्रों का कहना है कि दो दिन अमावस्या होने पर दूसरे दिन दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत होगा। 1 नवंबर को शुक्रवार है। स्वाति नक्षत्र

है। प्रीति और आयुष्मान योग है। इन सभी तथ्यों को देखा गया है। देश के 150 से अधिक पंचांगकारों का कहना है कि दीप पर्व 1 नवंबर को मनाना ही शास्त्र सम्मत होगा।

देश में दो प्रकार के पंचांग: आचार्य शर्मा- आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा वैदिक ने बताया यह लड़ाई पंचांगों की है। देश में दो प्रकार के पंचांग प्रकाशित होते हैं।

एक दृश्य गणित पर आधारित पंचांग और दूसरा लाघव पद्धति पर आधारित पंचांग। एक ट्रेडिशनल तो दूसरा कम्प्यूटराइज्ड है। ट्रेडिशनल पंचांगों की संख्या 7 या 8 हैं। वहीं कम्प्यूटराइज्ड पंचांगों की संख्या देशभर में 150 से अधिक हैं। सभी कम्प्यूटराइज्ड पांचागों का कहना है कि 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना धर्म शास्त्र अनुसार उचित है। पं. रामचंद्र शर्मा वैदिक। उन्होंने बताया कि सभी से चर्चा के बाद तय किया गया है कि इस बार 1 नवंबर को दीप पर्व मनाना तय किया गया है।

1 नवंबर को दीपावली तो दीपोत्सव 6 दिनों का

दीपावली 1 नवंबर को मनाई जा रही है इसलिए दीप पर्व छह दिन का होगा। धनत्रयोदशी 29 अक्टूबर को है, जो 30 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी। दीपदान 30 अक्टूबर को होगा, लेकिन रूप चतुर्दशी का उदयकालीन महत्व होने से चतुर्दशी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन, 2 को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज रहेगी।

सराफा में अब तक नहीं छपा दीपावली का पाना

दीपावली कब मनाई जाएगी इस संशय की वजह से सराफा में अब तक दीपावली का पाना तैयार नहीं हुआ है। एक व्यापारी ने कहा- हर बार अब तक पाना प्रकाशित हो जाता है। इस बार अलग-अलग मत होने से फिलहाल इसका प्रकाशन नहीं हुआ है।

राहुल गांधी की 'विजय संकल्प यात्रा' : बोले-

हरियाणा को नहीं चाहिए अडाणी सरकार

- प्रियंका बोलीं- प्रधानमंत्री 10 साल पुराने आरोप लगा रहे

नारायणगढ़ (एजेंसी)। राहुल गांधी की हरियाणा में दो दिन हरियाणा 'विजय संकल्प यात्रा' निकाल रहे हैं। सोमवार, 30 सितंबर को पहले दिन यह यात्रा नारायणगढ़ से शुरू हुई। राहुल ने नारायणगढ़ की जनसभा में कहा, हरियाणा में मुकाबला भाजपा-कांग्रेस का है। बाकी छोटी-छोटी पार्टियां सब भाजपा की हैं। अग्निवीर स्कीम जवानों की पेंशन चोरी का तरीका है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में अडाणी की सरकार नहीं चाहिए। किसानों, मजदूरों की सरकार बनेगी। जब भी मेरी जरूरत है, भाषण देना हो। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस यात्रा में राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 10 साल पुराने आरोप लगा रहे हैं।

बोधगया में बरसे बाबा बागेश्वर

हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता

गया (एजेंसी)। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के बोधगया में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बाबा बागेश्वर अपने 200 अनुयायियों को पिंडदान कराने के लिए गया में हैं। यहां पर

कथा के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमानित नहीं करते, लेकिन हिन्दू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी अपने मौलवियों को बेइज्जत नहीं करते हैं, लेकिन हमलोग करते हैं। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि लोगों के दिमाग में गलत बातें भरी जा रही हैं, जिसकी वजह से आज लोग श्राद्ध जैसे कर्मकांड को भी मजाक समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग के दिमाग में बहुत ही प्रायोजित तरीके से ब्रेन को वॉश करने के लिए शब्दों को पहुंचाया जा रहा है और भरा जा रहा है, इसलिए आज लोग श्राद्ध को भी हास्य समझते हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने इस दौरान यह भी कहा कि वह किसी के विरोध में नहीं हैं लेकिन उन्होंने 'हवस का पुजारी' सुना है, तो 'हवस का मौलवी' क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी किसी मुल्ला को अपने धर्म का मजाक उड़ाते हुए देखा है? उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमने हवस का पुजारी सुना है।

तिरुपति लड्डू केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें

नई दिल्ली (एजेंसी)। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा- 'जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें।'

बेंच ने कहा- जुलाई में लैब रिपोर्ट आई। वह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री एसआईटी जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है।

दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला- गरीब दलित को आईआईटी धनबाद में एडमिशन दो,ऐसा टैलेंट जाने नहीं दे सकते, फीस के पैसे नहीं जुटा पाया था

उत्तरप्रदेश के मुजफ्फरनगर का गरीब छात्र अतुल कुमार अब आईआईटी धनबाद में पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 30 सितंबर को दाखिला देने का आदेश दिया।

हरियाणा चुनाव प्रचार में सीएम योगी बोले

कांग्रेस ने तुष्टीकरण की हदें पार की, विकास के नाम अपने परिवार को आगे बढ़ाया

हरियाणा (एजेंसी)। योगी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि आपने देखा है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में कनेक्टिविटी का विकास हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस ने लोगों के लिए काम किया होता तो पीएम मोदी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन नहीं देना पड़ता।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान योगी ने कहा कि मैं बवानी खेड़ा की जनता का आभारी हूं जिन्होंने यहां कांग्रेस का खाता कभी नहीं खुलने दिया। उन्होंने कहा कि यहां के लोग जानते हैं कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो वे देश के साथ गद्दारी करेंगे। उन्होंने (कांग्रेस) अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश के विभाजन का समर्थन किया। तुष्टीकरण की हदें पार कर विकास के नाम पर केवल अपने घरों को आगे बढ़ाया। उन्होंन साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने देश को विकास नहीं बल्कि आतंकवाद और अराजकता दी।

जम्मू-कश्मीर की 40 सीटों पर आज वोटिंग

- आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स; आतंकी अफजल गुरू और इंजीनियर राशिद के भाई चुनावी मैदान में

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण में आज मंगलवार (1 अक्टूबर) को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें 39.18 लाख वोटर्स शामिल होंगे। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, आखिरी फेज 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से केन्द्रीय मंत्री शिवराज ने की भेंट,बोले-

पीएम आवास योजना का नया सर्वे अगले हफ्ते

दो पहिया वाहन, मोबाइल, 15 हजार की आमदनी पर भी मिलेंगे आवास

भोपाल (नप्र)। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते से नए सिरे से सर्वे शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपात्रता की चार शर्तें हटा दी हैं। जो शर्तें हटाई गई हैं, उसके बाद मोटर साइकिल, फोन और 10 हजार की आमदनी रखने वाले लोगों को भी योजना में आवास मिल सकेंगे। साथ ही, किसानों को भी इस योजना का लाभ देने के लिए शर्तों में रियायत दी गई है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने ये बातें सोमवार को मीडिया से चर्चा में कहीं। उन्होंने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री निवास मे सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। शिवराज ने कहा कि मुलाकात के दौरान केंद्र की योजनाओं का लाभ कैसे एमपी के लोगों को अधिकतम मिले, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में आवास प्लस का सर्वे हुआ था। अब अगले महीने फिर सर्वे शुरू होगा, जिसमें जो लोग पात्रता की श्रेणी से बाहर थे, उन्हें भी पीएम आवास मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

खाद्य तेल, चावल में किसानों को होगा फायदा- शिवराज ने कहा कि सरकार ने पाम ऑइल से इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो की है। इससे बाहर के देशों से सस्ता तेल आता था। सोयाबीन के दाम कम हो गए थे। अब 27.5 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी तय की है, जिससे भारत के बाहर से आने वाला तेल सस्ता न आए और इसके कारण ऑइल सीड सोयाबीन, सरसों, मूंगफली के दाम किसानों को ठीक मिले। अब इससे देश के किसानों को तेल की अच्छी कीमत मिल सकेगी। सरसों मूंगफली पर अच्छी कीमत मिले, इसलिए भी यह फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि बासमती चावल पर पहले मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइज लगती थी, उसे खत्म कर दिया है। इससे बासमती चावल के दाम की और अच्छी कीमत मिलेगी। इसके लिए भी रणनीति तय की गई है। सामान्य चावल पर एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध था, उसे हटा दिया है, ताकि यहां का चावल बाहर जाए और अच्छे दाम मिलें। सोयाबीन एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया है। मसूर, उड़द, तुअर जैसी दालें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी।

लाड़ली बहना योजना हर राज्य लागू कर रहे- यह योजना हर राज्य में किसी न किसी रूप में लागू की जा रही है। हमारे विरोधी भी इसे लागू कर रहे हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना वहां की सरकार लाई है। बीजेपी अंतरात्मा से यह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र, एमपी, छग में यह योजना चल रही है और समय पर पैसे दिए जा रहे हैं।

ये शर्तें हटाई गईं

पहले दो पहिया वाहन रखने वालों को पीएम आवास नहीं मिलते थे। अब जिनके पास दो पहिया हैं, वे पात्रता की श्रेणी में आएंगे।

पहले जिनकी आमदनी दस हजार से ज्यादा हो तो पीएम आवास नहीं देते थे। अब लखपति दीदी बना रहे हैं, इसलिए तय किया है कि 15 हजार तक आमदनी पर भी मिलेगा।

पहले अगर किसी के पास फोन (मोबाइल) है, तो पीएम आवास की पात्रता नहीं थी। अब फोन है, तो भी लाभ मिल सकेगा।

यह भी तय हुआ है कि अगर किसी किसान के पास ढाई एकड़ तक सिंचित और पांच एकड़ तक असिंचित जमीन हो, तो पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा।

एमपी में कैसे अधिकतम लाभ उठाएं, इस पर चर्चा

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं का अधिकतम लाभ कैसे एमपी उठाएं, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि साढ़े तीन लाख आवास पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत एमपी के लोगों के लिए मंजूर किए गए हैं। पीएम जनमन योजना में एमपी में 311 सड़कें बनेंगी। इसे मंजूरी दी गई है। किसानों के हित में अन्य फैसलों पर भी चर्चा हुई है।

'सरिता स्मृति अलंकरण' घोषित

भोपाल (नप्र)। दुष्यंत संग्रहालय भोपाल में आयोजित कार्यक्रम 'सरिता स्मृति लोकार्पण' प्रसंग में उनके द्वारा लिखे गए अग्रलेखों के संकलन का विमोचन प्रख्यात रंगकर्मी एवं अभिनेता राजीव वर्मा द्वारा किया गया। इस कृति का संपादन लेखक-कवि मोहन सगोरिया ने किया है। मंच पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, पत्रकार डॉ राकेश पाठक, कथाकार हरि भटनागर, कवि-पत्रकार सुधीरसक्सेना और वरिष्ठ लेखक राजेंद्र कोठारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधान संपादक 'दुनिया इन दिनों' डॉ. सुधीर सक्सेना ने 'सरिता स्मृति अलंकरण' के शुभारंभ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह अलंकरण साहित्य-संस्कृति ही नहीं वरन् विज्ञान, खेल, संगीत, पर्यावरण, पत्रकारिता, फिल्म और थिएटर के साथ अन्य विधाओं में भी प्रदान किया जाएगा। अलंकरण समारोह प्रथम वर्ष में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होगा क्योंकि रायपुर सरिता सक्सेना की जन्मभूमि है। तत्पश्चात यह श्रृंखला देश भर में चलाई जाएगी। अलंकरण देने लिए व्यक्ति का चुनाव जूरी द्वारा किया जाएगा। इस जूरी में वरिष्ठ लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता रघुराज सिंह भोपाल, वरिष्ठ मीडियाकर्मी एवं पत्रकार राजेश बादल भोपाल, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन दिल्ली और पत्रकार कुमुद जैन हैदराबाद सम्मिलित होंगे। पत्रकार-संपादक सरिता सक्सेना की स्मृति में हुए इस भव्य आयोजन में युवा संगीतकार अजय मिश्रा और रामेश्वर बंसल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गीतों की सांगीतिक प्रस्तुति दी। सरिता सक्सेना की पत्रकारिता के क्षेत्र में अवदान को रेखांकित करते हुए मंचासीन अतिथियों ने तथा आगंतुकों ने उन्हें महिला पत्रकारों की श्रेणी में अग्र पंक्ति में रखा।

मंच से रेखांकित किया गया कि सरिता सक्सेना बगैर किसी लोकप्रियता के लालच से निष्पृह रहकर शांत और चुपचाप अपना कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संपादक थीं।

उन्होंने अपने कार्यकाल में समकालीन विषयों पर बेबाकी से अपनी क़लम चलाई। वे देश, देशज और देशांतर मुद्दों पर प्राथमिक तौर पर लिखती थीं। उनके संपादकीय लेख आज भी प्रासंगिक है।

सुरक्षाकर्मी ने सीपीआर देकर बचाई विधायक की जान

पुलिस ट्रेनिंग में सीखी टेक्नीक काम आई; सीएम ने प्रमोशन-रिवॉर्ड का किया ऐलान

भोपाल (नप्र)। 24 सितंबर के सुबह 10.45 बजे। इंदौर जिले की राऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मधु वर्मा घर में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुन रहे थे। अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। वहां मौजूद पीएसओ (पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर) अरुण सिंह भदौरिया, पीए और एक अन्य सहयोगी प्राइवेट कार से विधायक को फौरन अस्पताल लेकर रवाना हुए। इस बीच रास्ते भर विधायक को उनके पीएसओ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) भी देते रहे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की तो विधायक के हार्ट में ब्लॉकेज पाया गया। इसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। विधायक मधु वर्मा अभी खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों के साथ विधायक की जान बचाने में पीएसओ की भी अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की है।

जिनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें सुरक्षित कर पाया: पीएसओ ने पुलिस ट्रेनिंग में सीपीआर देने की टेक्नीक सीखी थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी मां का निधन हार्ट अटैक से हुआ था। उन्हें भिंड से 56 किलोमीटर दूर ग्वालियर ले जा रहे थे। सीपीआर भी दी, लेकिन मां को बचा नहीं सके। भिंड में हार्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं है। पीएसओ आगे कहते हैं, मां की असमय डेथ के बाद यह बात हमेशा मन में रहती है कि किसी को भी अगर हार्ट अटैक आए तो उसे तुरंत सीपीआर देकर अस्पताल पहुंचा दिया जाए। विधायक जी सुरक्षित हैं, ये सोचकर मन में संतोष हो रहा है। जिनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, उन्हें सुरक्षित कर पाया, ये बात बहुत सुकून दे रही है।सीएम ने पीएसओ अरुण भदौरिया की तारीफ की। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के साथ उन्हें 50 हजार रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है।

सीपीआर क्या है, यह कैसे काम करता है: यह एक लाइफ सेविंग टेक्नीक है। इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक (दिल का दौरा) के दौरान किया जाता है। अगर किसी इंसान के दिल की धड़कन बंद हो जाए तो घर से अस्पताल जाने के दौरान सीपीआर लाइफ सेविंग का काम करता है।

ग्वालियर में एएसआई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, गोली मारी

रंजिश के चलते सुबह पड़ोसी की मां ने धमकाया, शाम को बेटे ने कर दिया हमला

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में एक एएसआई (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर) पर जानलेवा हमला हो गया। पहले उन्हें लोहे की रॉड और बैट से सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। जब आसपास लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो एक बदमाश ने कट्टा निकालकर गोली मार दी। गोली एएसआई की कमर को छूते हुए निकल गई। घटना रविवार शाम को कोटेश्वर कॉलोनी स्थित गैस गोदाम के पीछे दरगाह के पास की है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक हमलावर भाग निकले। पुलिस ने घायल दरोगा को उपचार के लिए भर्ती कराया है। सोमवार दोपहर को पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

मंदिर जाते वक्त रास्ते में हो गया हमला: उपनगर ग्वालियर कोटेश्वर कॉलोनी निवासी बृजेश पुत्र राधेश्याम यादव (38) पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) हैं। बृजेश शिवपुरी जिले में पदस्थ हैं। फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं। रविवार को बृजेश यादव घर के पास ही मंदिर दर्शन करने गए थे। रास्ते में चेतन पांडेय, प्रियांशु दुबे, सत्यम दुबे समेत उनके 5 से 6 साथियों ने रास्ता रोक लिया, वे गाली गलौज करने लगे। जब विरोध किया, तो उन्होंने मारपीट कर दी। हमलावरों ने पहले लोहे की छड़ से सिर पर वार किए। फिर बेसबॉल के बैट से भी पीटा। इस बीच एक हमलावर ने कट्टे से एएसआई को गोली मार दी, जो उनके कमर के पास से रगड़ते हुए निकल गई। मारपीट होते देखकर कुछ लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया तो उन्हें भी धमकाते हुए आरोपी भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल एएसआई को अस्पताल पहुंचाकर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। घायल के परिजन ने बताया कि सुबह प्रियांशु दुबे की मां हेमलता ने धमकी दी थी कि उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। शाम को उसके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर दारोगा को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया।

स्ट्रीट डॉग को लेकर हुई थी कहासुनी

कुछ दिनों पहले एएसआई के बेटे को एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। इससे गुस्साए एएसआई ने स्ट्रीट डॉग को पीटा था। तभी वहां पर पड़ोस में रहने वाले चेतन और प्रियांशु ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई थी। तभी से इनके बीच रंजिश चली आ रही है। होली के बाद भी चेतन और प्रियांशु ने एएसआई पर गोलियां चलाई थीं। जिसे लेकर केस दर्ज हुआ था और संभवतः इसी के चलते वापस हमला किया है।

ग्वालियर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह तोमर बोले...

घायल दारोगा को उपचार के लिए भर्ती कराया है। हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में उनके घरों पर दबिश दी गई है।

विश्व हिंदू परिषद मध्य भारत के पूर्व प्रान्त मंत्री डॉ. सुरेंद्र सिंह को गौ विज्ञान विभाग भोपाल क्षेत्र (मध्य प्रदेश - छत्तीसगढ़) का प्रमुख नियुक्त किया गया है। डॉ. सुरेंद्र सिंह को यह महत्वपूर्ण दायित्व विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग की 27 से 29 सितंबर 2024 तक अमृतसर (पंजाब) में संपन्न बैठक में सौंपा गया। डॉ. सुरेंद्र विहिप के वरिष्ठ सदस्य हैं।

मासूम से रेप-हत्या की आरोपी मां-बेटी

बच्ची के परिवार के साथ आंसू बहाती रहीं, बोलीं- बाहरी ने ही किया अपहरण

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले अतुल भालसे की मां बसंती और बहन चंचल का जेल जाने से पहले का आखिरी वीडियो सामने आया है। अतुल के गुनाह पर परदा डालने वह लगातार बच्ची के परिवार के साथ रहीं, झूठे आंसू बहाती रहीं। गुमराह करने दावा करती रहीं कि मल्टी का कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। बच्ची का अपहरण किसी बाहरी ने ही किया है। वीडियो में मां-बेटी दोषियों को फांसी देने तक की मांग करती रहीं। सोमवार को आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

आरोपी की रिमांड के दौरान पुलिस ने क्या कुछ किया

पुलिस ने आरोपी के फ्लैट की शनिवार को एक बार फिर सर्चिंग की। जहां से घटना के समय उसके द्वारा पहना हुआ लोअर सहित अंडर गार्मेंट्स और एक शर्ट जब्त की गई। बच्ची के कपड़ों की जब्ती भी आरोपी के फ्लैट से ही शनिवार को की। उसकी डीएनए सैंप्लिंग भी पुलिस ने करा ली है। मां और बहन के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया है। तीनों मोबाइल परीक्षण के लिए लैब भेज दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से सभी जरूरी पूछताछ की जा चुकी है। आज अतुल की रिमांड खत्म होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।

सूनेपन का उठाया था फायदा: आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि फागिंग के कारण लोगों ने अपने फ्लैट के गेट बंद कर लिए थे। आम तौर पर मल्टी में भीड़भाड़ रहती है। मंगलवार की दोपहर बच्ची धुएं के कारण बरामदे में अकेली दिखी। यह मौका देख उसकी नीयत खराब हो गई। उसने बच्ची को फ्लैट में खींच लिया। इस समय उसकी मां और बहन दोनों काम पर गई थीं। यहां उसने बच्ची के साथ ज्यादती की। मासूम की तबीयत बिगड़ी तो इससे वह घबरा गया, पहले उसका मुंह दबाया और बाद में गला घोंट दिया।

मां के लौटते ही बोला था-बच्ची मार दी

मंगलवार की दोपहर को आरोपी की मां जब काम से लौटी तब उसने पूरा घटनाक्रम मां को बता दिया था। मां ने बहन के आने पर उसे भी मामले की जानकारी दी। बॉडी को ठिकाने लगा पाता इससे पहले ही मल्टी में बच्ची को तलाश करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई। इससे उसे शव को ठिकाने लगाने का मौका नहीं मिला।

पानी की टंकी में रखा था शव

मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात शव को कपड़े में बांधकर पानी की टंकी में रख दिया। ऐसा करने की बात उसकी मां ने ही कही थी। बाद में पानी की टंकी सहित बॉडी ठिकाने लगाने का प्लान था। लेकिन पुलिस मौके से हटी ही नहीं। मल्टी के चारों और पुलिस बल तैनात रहा।

पिटने के बाद भाजपा पार्षद और परिवार सदमे में

भोपाल में अरविंद वर्मा बोले- गुमठी विरोधी मुहिम का बदला लिया, पार्टी ने दिया नोटिस

भोपाल (नप्र)। भोपाल के शाहपुरा हॉकर्स में वार्ड 48 से बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा को पीटे जाने के मामले में चूना भट्टी पुलिस जांच में जुटी है। इसी बीच, पार्षद वर्मा का वीडियो सामने आया है। वीडियो में वर्मा ने कहा, मैंने गुमठी विरोधी मुहिम छेड़ रखी है, इसलिए हमला कराया गया है। इधर, बीजेपी ने पार्षद वर्मा को नोटिस जारी किया है। बता दें कि रविवार शाम शाहपुरा हॉकर्स पर सास-बहू ने पार्षद वर्मा की पिटाई कर दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। विवाद के बाद दोनों महिलाएं और पार्षद थाने पहुंच गए। यहां भी दोनों पक्षों में बहस हुई। पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं, महिलाओं के आवेदन पर जांच की जा रही है।

नौकरी छोड़कर पार्षद बना, डरूंगा नहीं

महिलाओं द्वारा पार्षद को पीटने के दो वीडियो रविवार को सामने आए थे। वहीं, सोमवार को पार्षद वर्मा ने भी अपना 3.29 मिनट का वीडियो जारी किया। वर्मा ने कहा- मैं अपने परिवार में पहला इंजीनियर हूं। पार्षद बनने से पहले मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। नौकरी छोड़कर राजनीति में आया। पार्षद बनने से पहले ही सोच लिया था कि अपने वार्ड को आदर्श व गुमठी मुक्त बनाऊंगा। मैं गुमटी माफिया के कृत्यों से आहत हुआ हूं। पार्षद बनते से ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चालू कर दी थी। इस कारण मुझे बुलडोजर पार्षद का नाम दिया गया था। इसे सराहना भी मिली थी।

संपादकीय

सीतारमन के खिलाफ केस के मायने

कर्नाटक में बेंगलुरू की एक अदालत द्वारा इलेक्टोरल बांड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ केस दायर करने का आदेश राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुडा मामले में लोकायुक्त द्वारा मामला दर्ज करने के राजनीतिक जवाब के रूप में ज्यादा देखा जा रहा है। इसका कारण यह है कि जिस इलेक्टोरल बांड मामले में यह केस दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसे फरवरी में ही असंवैधानिक बता चुका है। दूसरे, निर्मला सीतारमन पर और कोई आरोप भले लगे हो, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। गौरतलब है कि बेंगलुरु की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एक संस्था जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। जेएसपी द्वारा अप्रैल 2024 में दाखिल शिकायत में जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में निर्मला सीतारमन के अलावा ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के कई नेताओं, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र को भी पार्टी बनाया गया है। शिकायत में आरोप है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले गए। इस खबर के सामने आते ही खुद भ्रष्टाचार के केस में फंसे राज्य के मुख्यामंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। सिद्धारमैया के खिलाफ राज्य के लोकायुक्त ने मुडा प्लॉट हेराफेरी मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया है और विपक्षी भाजपा और जेडीएस उनसे इस्तीफा मांग रही है। ऐसे में संदेश यह जा रहा है कि कर्नाटक सरकार के इशारे पर ही बदले की कार्रवाई के रूप में सीतारमन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इलेक्टोरल बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लोकसभा चुनाव के पहले सीतारमन ने कहा था कि हम इलेक्टोरल बांड स्कीम वापस लेकर आएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। इलेक्टोरल बांड योजना की सबसे बड़ी खामी यह थी कि इसमें दूसरे लोगों के लिए गोपनीयता रखी गई थी, लेकिन सरकार को सब पता होता था कि इलेक्टोरल बांड के जरिए किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। इसके आंकड़े भी सामने आ चुके है। इसके पहले भी सरकार का दावा था कि इस योजना से चुनावी चंदे में पारदार्शिता आएगी, जिसे कोर्ट ने नहीं माना। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि निचली अदालत ने क्या सोचकर निर्मला सीतारमन के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया? निश्चय ही केन्द्रीय वित्त मंत्री इस आदेश के खिलाफ ऊंची अदालत में जा सकती हैं। यहां मुद्दा राजनीतिक बदले भुनाने का है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति आम होती जा रही है कि किसी भी नेता के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता वाले राज्य में पुलिस मामले दर्ज कर लेती हैं। इसमें सत्तारूढ़ दल की स्वीकृति होती है। भले उसके पास अपराध के कोई प्रमाण हो न हों। इसका एकमात्र मकसद सामने वाले को फंसाना है और सम्बन्धित व्यक्ति अगर पद पर हो तो उससे इस्तीफा मांगना है। हालांकि आजकल तो ऐसे मामले में कोई इस्तीफा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से जेल जाने के बाद भी त्यागपत्र नहीं दिया।

नजरिया

राजीव खंडेलवाल

(लेखक, कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

एक देश एक चुनाव : 'संघीय ढांचे पर अतिक्रमण' कैसे?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार 73वें स्वाधीनता दिवस (वर्ष 2019) के अवसर पर ''लाल किले'' से संबोधित करते हुए देश को ''वन नेशन वन इलेक्शन'' ('एक देश एक चुनाव) का वैचारिक उपक्रम'' दिया। इस संबंध में वर्ष 1983 से ही भिन्न-भिन्न समय में चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग एवं संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता में एक वर्ष पूर्व गठित कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को रूबरू कैबिनेट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस पर देश का अभिमत लगभग सीधा-सीधा विभाजित है। आज जब मैं इस विषय पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी, स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष, प्रसिद्ध सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव व प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी के विचारों को पढ़-सुन रहा था, तब मुझे लगा कि इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ''क्या इससे संविधान के मूलभूत (बुनियादी) ढांचा (उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती में प्रतिपादित) में परिवर्तन होगा अथवा यह संघीय ढांचे पर अतिक्रमण है'? वस्तुतः इसकी व्याख्या व आलोचना गलत रूप से की जा रही है। इस संबंध में राहुल गांधी का ट्वीट है ''भारत राज्यों का एक संघ है।' 'एक देश-एक चुनाव'' संघ और इसके सभी राज्य पर हमला है''। ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर वर्ष 1950 से लागू संघीय संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर प्रकाश डालना जरूरी हो गया है।

बेशक यह मुद्दा आज बहस के केंद्र में है। परन्तु स्वाधीन भारत के प्रारंभिक चरणों में वर्ष 1952 से 1967 तक हुए चार आम चुनावों में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ ही करवाए गए थे (एक अपवाद को छोड़कर जब पहली बार वर्ष 1960 में केरल विधानसभा के मध्यावधि चुनाव कराने से यह क्रम पहली बार टूटा)। एक साथ चुनाव कराने का क्रम लगातार तब टूटा, जब वर्ष 1968-69 में व उसके बाद समय-समय पर दोनों राज्यों की विधानसभाएँ विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। बड़े पैमाने पर वर्ष 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन होने। खासकर देश में वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा चुनाव भी समय से पहले कराये गए थे। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब चार बार एक साथ चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं, तो अब पुनः उक्त स्थिति को पुर्नस्थापित करने में समस्या क्या है?

जनसंघ से लेकर भाजपा और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक सपना रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, 'विविधता में अनेकता लिये हुए'' भारत देश की अखंडता को एक सूत्र में बांधने के लिए ''एक देश-एक विधान'' ''एक निशान'', ''एक मोबिलिटी कार्ड, (एनसीएमसी)'' एक

पहचान (आधार कार्ड) ''एक राशन कार्ड'', ''एक कर'', ''एक शिक्षा नीति'', एवं एक देश-एक ग्रिड'का होना आवश्यक है। इसी कड़ी में एक देश-एक चुनाव की नीति पर मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। इसके विरोध में विपक्षी नेताओं ने वन नेशन-वन इनकम, वन एजुकेशन, वन इलाज का शिगूफा छोड़ दिया है। यहां पर यह नीति कितनी सही है या गलत, धरातल पर लागू करने में कितने व्यावहारिक व संवैधानिक रुकावटें हैं, इन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

योगेन्द्र यादव व एस वाई कुरैशी ने कमेटी की रिपोर्ट की कुछ कमियों को जो इंगित किया है वही सही है। परन्तु योगेन्द्र यादव का यह कहना कि यह 'शासक की लोकतंत्र को कमजोर करने की डिजाइन' है। यह संसदीय शासन प्रणाली में निहित विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाब देही के मूल सिद्धांत को बिगाड़ देगा। साथ ही यह संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करता प्रतीत होता है। ये तीनों ही बातें तथ्यात्मक व संवैधानिक दृष्टि से से गलत है। इसका सीधा जवाब है कि प्रारंभिक 20 वर्षों तक जब एक साथ चुनाव हो रहे थे, क्या देश में लोकतंत्र व संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा था? तब देश के किसी भी शख्स ने एक साथ चुनाव के विरोध में एक शब्द भी नहीं कहा। कुरैशी ने जरूर कुछ मुद्दों का व्यवहारिक हल निकालने का आग्रह किया है।

इसके विरोध में एक बात और कही जाती है। जिस प्रकार जीएसटी को लागू किया गया परन्तु 'एक देश एक कर' की बात पूरी तरह से लागू नहीं हो पायी। 'एक दर' की बजाए विभिन्न दरों के साथ पेट्रोलियम उत्पाद को भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। क्या इसी प्रकार एक देश-एक चुनाव पूरी तरह से आज भी सरकार लागू करने नहीं जा रही है? यह बात सही है। क्योंकि कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में पंचायतों के चुनाव आम चुनाव के बाद 100 दिन के अंदर कराये जाने की बात की गई है, जो समझ से परे है। एक बात और जो इस कदम के विरूद्ध कही जा रही है, देश के एक साथ विधानसभा-लोकसभा को वोट देने पर देश में साक्षरता का स्तर कम होने के कारण लोग विवेक से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका कुछ फायदा केन्द्र में बैठी सरकार की पार्टी को होता है। विशेषकर क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है। इस संबंध में अभी हाल के हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव का उल्लेख किया जाता है। यदि 1952 से लेकर 1967 तक साक्षरता की दर को देखे तो आज वह लगभग दो गुनी हो गई है। जब उस समय 20 साल तक मतदाता के विवेक पर प्रश्न साक्षरता के आधार पर नहीं उठाया गया, तब इस आधार पर आज प्रश्न उठाना कितना जायज है? एक और आधार ''राज्य के मुद्दों'' पर केंद्र के मुद्दे हावी हो जाएंगे, एक साथ चुनाव कराने में? वस्तुतः यह जनता के विवेक पर ही प्रश्न-चिन्ह लगाने समान है?

यद्यपि आज की राजनीति में ''एक्शन की बजाय परसेप्शन'' का महत्व ज्यादा है, जिसे बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर है। उनके मुकाबले सिर्फ केजरीवाल ही ठहर पाते है। इसके लिए भी एक्शन करते हुए दिखना जरूर पड़ता है। परंतु इस मुद्दे को लेकर मोदी चूक गये लगते है। क्योंकि 'एक देश-एक चुनाव' को लेकर प्रथम अवसर मिलने पर ही एक्सन कर परसेप्शन क्यों नहीं बनाया जा रहा है? पिछले एक साल में लें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ही ले लो 7 फेस में लोकसभा चुनाव की हुए चुनावी प्रक्रिया की अवधि कम की जा सकती थी। उड़ीसा विधानसभा के साथ ही महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड के चुनाव लोकसभा के साथ एक साथ कराया जा सकते थे, यदि चुनाव आयोग इनकी अवधि को 6 महीने आगे पीछे घटा बड़ा कर लेता, जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। वर्ष 2022 में गुजरात के साथ हिमाचल के भी चुनाव कराये जा सकते थे, जो पहले होते थे। तब शायद जनता के मन यह परसेप्शन जरूर जाता कि सरकार वास्तव में इस विषय पर गंभीर है और वह बिना संवैधानिक संशोधन किये इस दिशा में जो कदम उठा सकती है, उठा रही है। इसलिए कुछ लोग इसे सरकार का इस विषय पर गंभीर न होकर नरेन्द्र मोदी का शिगूफा मात्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके लिए दोनों सदनों में आवश्यक संख्या बल से एनडीए कोसों दूर है। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीच में विधानसभा भंग होने पर उसका चुनाव 5 साल के लिए न किये जाकर शेष अवधि के प्रावधान के लिए किया है। शायद यह प्रस्तावित संशोधन जरूर संविधान की मूल अवधारणा को चोट पहुंचा सकता है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की राय भी ली जा सकती है।

राजनीति

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

जम्मू कश्मीर चुनाव से चिंताजनक संकेत

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दो चरण समाप्त हो चुके हैं, परिणाम जो भी आये, वहां से काफी चिंताजनक और भविष्य की दृष्टि से डरावने संकेत मिल रहे हैं। लंबे समय से वहां की राजनीति में स्थापित प्रमुख पार्टियां नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी तथा हाल में खड़ी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आदि द्वारा उठाए जा रहे विषय और मुद्दे देश की एकता - अखंडता और जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल अस्वीकार्य होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अब संसद हमले के अभियुक्त अफजल गुरु की फांसी को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु की फांसी में जम्मू सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो हम नहीं देते। वे यही नहीं रुके और कहा कि मुझे नहीं लगता कि उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। ज.. हमने कई बार देखा है कि फांसी की सजा दे दी जाती है और बाद में यह पता चलता है कि व्यक्ति निर्दोष था। यह भारत की न्याय व्यवस्था के साथ संपूर्ण सत्ता के विरुद्ध बयान है। अफ़ज़ल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही पार्टियों ने यह राग अलापना शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती अफजल गुरु की फांसी को अन्याय बताती रही हैं और उनकी प्रतिक्रिया भी यही है। ज्यादातर नेता जम्मू कश्मीर और इंडिया शब्द बोलने लगे हैं। यानी जम्मू कश्मीर और इंडिया या भारत दो अलग-अलग एंटायटी हैं। मेहबूबा मुफ्ती ने जमात ए इस्लामी से प्रतिबंध हटाकर उसे चुनाव लड़ने की अनुमति देने की मांग की है। जैसी जानकारी है प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्य निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। ये सारी पार्टियां पाकिस्तान के एक पक्ष होने से लेकर धारा 370 हटाने के पूर्व स्थिति बहाली के साथ भारत से स्वायत्त और अनेक मामलों में स्वतंत्र अवस्था में होने का वायदा कर रहे हैं। नेशनल कांफ्रेंस के घोषणा पत्र में इन बातों के साथ शंकराचार्य पर्वत को तख्त ए सुलेमान और हरी पर्वत को कोहे मारन नाम देने की घोषणा है। नेशनल कांफ्रेंस की चर्चा इसलिए कि देश में ऐसी छवि बनाई गई कि यह पार्टी और अब्दुल्ला परिवार अन्यों से ज्यादा लिबरल और भारत समर्थक है। आप पार्टियों के घोषणा पत्र, उनके भाषणों के स्थानीय समाचार पत्रों,वेबसाइटों आदि से जानकारी लें तो पता चल जाएगा कि चुनाव में क्या हो रहा है।

अफजल गुरु 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हमले के दो दिनों बाद 15 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ। 18 दिसंबर, 2002 को अफजल गुरु, एसआर गिलानी और शौकत हसन गुरु को फांसी की सजा दी गई तथा एक आरोपी अहसान गुरु को बरी किया गया। 4 अगस्त, 2005 को उच्चतम न्यायालय ने अफजल गुरु की सजा को बनाए रखा तथा शौकत हसन गुरु की फांसी की सजा 10 साल कठोर कारावास में परिणत कर दिया। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर, 2006 को अफजल गुरु को फांसी देने का आदेश दिया। अफजल गुरु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दया याचिका भी 12 जनवरी, 2007 को खारिज हो गई। काफी समय तक उसे फांसी नहीं चढ़ाने पर आम लोगों और भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और काफी बहस चली। 23 जनवरी, 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल गुरु की दया याचिका खारिज कर गृह मंत्रालय को वापस भेज दिया। यह इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि कांग्रेस को लगा कि चुनाव में लेने के देने पड़ सकते हैं। तब 9 फरवरी, 2013 को तिहाड़ जेल में सुबह अफजल को फांसी दे दी गई। इनका जिक्र इसलिए जरूरी है कि देश के ध्यान में रहे कि न्यायिक प्रक्रिया के सारे विकल्प अपनाने के बावजूद लंबे समय बाद वह फांसी पर चढ़ा। उसे आज अगर जम्मू कश्मीर में पार्टियां मुद्दा बना रही हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि वहां ये किस तरह का माहौल बना रहे हैं। क्या यह संसद हमले को सही ठहराना नहीं है? क्या यह आतंकवादी के कृत्य का समर्थन नहीं है? इन सबसे परे मुख्य प्रश्न यह है कि आखिर इससे जम्मू कश्मीर का वातावरण कैसा बनाने की कोशिश हो रही है?

वैसे इसमें आश्चर्य की भी कोई बात नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर की ये पार्टियां तभी से अफजल गुरु की फांसी का विरोध करती रही है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और विधानसभा में चर्चा में अफजल को निर्दोष कहा गया तथा फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ। जम्मू कश्मीर को हिंसा में झोंकने की कोशिश हुई सरकार मूकदर्शक बनी रही। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस का नेशनल कांफ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ है और उसी के कार्यकाल में फांसी की सजा हुई पर वह इसके विरुद्ध वक्तव्य देने से भी बच रही है। कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस की उन घोषणाओं का भी विरोध नहीं किया जो इस्लामी कट्टरवाद और अलगाववाद को आक्रामक रुप से उभारने की चेष्टा है। जमात ए इस्लामी के चुनाव लड़ने की मांग तथा पाकिस्तान से वार्ता या फिर 370 के पूर्व स्थिति या हिंदू धार्मिक स्थानों के नाम बदलने आदि की घोषणाएं इसी को प्रमाणित करतीं हैं। कश्मीर में पाकिस्तान या आजादी समर्थकों का मूल तर्क यही रहा है कि मुस्लिम बहुल होने के कारण इस्लाम के रूप में इसकी अलग पहचान है और उसी रूप में इसका अस्तित्व बना रहना चाहिए। धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में विधायी व प्रशासनिक से लेकर आंतरिक राजनीतिक संरचना आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था, लोगों के जनजीवन पर अत्यंत सकारात्मक हुआ है। इसमें आम आदमी सोचने लगा है कि क्या अभी तक हमें गफलत में रखा गया? इसमें इन पार्टियों की खतरनाक सोच है कि कश्मीर की इस्लामी राज्य के रूप में पहचान तथा विशेष अधिकार के साथ स्वायत्तता बड़े वर्ग के अंदर पुराने दौर की ओर लौटने कासमर्थक बनाएगा जिसका चुनावी लाभ मिलेगा। इस पर नेशनल कौन्फ्रेंस और पीडीपी में प्रतिस्पर्धा है। जमात ए इस्लामी को लेकर जब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहले वे चुनावों को हराम यानी निषिद्ध मानते थे और अब हलाल यानी स्वीकार्य मानने लगे हैं तो मेहबूबा ने उन पर हमला करते हुए कहा कि 1987 में जमात ए इस्लामी और अन्य समूहों ने चुनावों में भाग लेने की कोशिश की, तो एनसी ने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं कीं क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई तीसरी ताकत उभरे। उनके कारण ही आखिर में जेईआई और अन्य समूहों ने चुनाव का बहिष्कार किया। महबूबा ने कहा कि उमर की पार्टी ने ही चुनाव के संबंध में हराम और हलाल की यह कहानी शुरू की थी। उनकी पंक्तियां देखिए 1947 में जब दिवंगत शेख अब्दुल्ला पहली बार जम्मू-कश्मीर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बने थे और मुख्यमंत्री बने, तो चुनाव हलाल थे। जब उन्हें पद से हटा दिया गया, तो 22 साल तक चुनाव हराम हो गए। 1975 में जब वे सत्ता में लौटे, तो चुनाव अचानक फिर से हलाल हो गए।

कहने की आवश्यकता नहीं कि मजहबी अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान को अभी भी ये अपने राजनीतिक हैसियत के लिए आवश्यक मानते हैं। धारा 370 हटाने और मोदी सरकार की परवर्ती नीतियों से यह स्थिति लगभग समाप्त है, तो अस्तित्व का ध्यान रखते हुए फिर पुरानी स्थिति लाने की कुचेष्टा है, जिससे जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों से अलग सोच वाला हिंसा और अलगाववाद से ग्रस्त तथा तीसरी पार्टी यानी पाकिस्तान के मान्य अधिकारों की भावना वाला प्रदेश बने। चुनाव में पार्टियों का राजनीतिक स्वार्थ है किंतु देश की दृष्टि से इस तरह के विचार और व्यवहार का सभी पार्टियों, नेताओं और बुद्धिजीवियों को एक स्वर में विरोध करना चाहिए।

भगवान कृष्ण के मानव रूपी जीवन की सार्थक पुष्टि

पुस्तक चर्चा

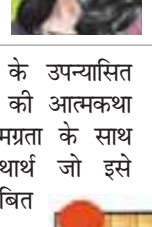

माधुरी व्यास 'नवप्रभा'

समीक्षक

लेखक मनु शर्मा के उपन्यासित श्रृंखला में कृष्ण की आत्मकथा संपूर्णता और समग्रता के साथ प्रस्तुत एक ऐसा यथार्थ जो इसे उपनिषदीय कृति साबित करता है।

यह पुस्तक कुल 8 भागों यथा-नारद की भविष्यवाणी, दुरभीसंधि, द्वारका की स्थापना, लाक्षागृह, खांडवदाह, राजसूय यज्ञ, संघर्ष एवं अंतिम भाग प्रलय में संकलित है जिसमे कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन का चित्रांकन बिल्कुल नवीन दृष्टिकोण से इसप्रकार किया गया है कि पाठक स्वयं को पत्रों के बीच महसूस करने लगता है।

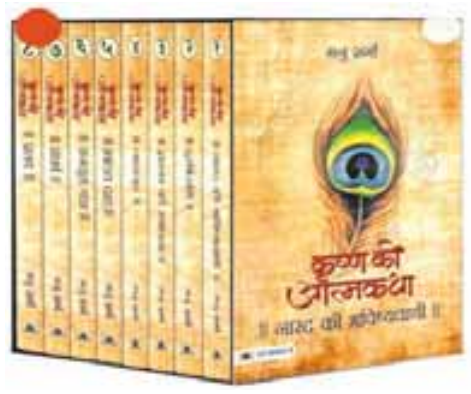

भगवान के जीवन की प्रत्येक घटना को चमत्कार नहीं बल्कि वास्तविकता की कसौटी पर साबित कर लेखक ने अपने दृष्टिकोण से व्याख्या की है। एक साधारण मनुष्य का ईश्वर स्वरूप में परिवर्तन सहज रूप से प्रस्तुत किया गया है ।इस पुस्तक में छंदक एक ऐसा चरित्र है जिसको कभी किसी भी रूप में हमने कहीं भी न कभी सुना न धारावाहिकों में देखा। यह एक ऐसा काल्पनिक चरित्र है जो कृष्ण का प्रतिरूप ही है । जो साधारण प्रजा का ऐसा रूप है जो घटनाओं का पूर्वाभास करता था। घटनाओं की कड़ियों को जोड़ता हुआ लगता है और फिर कथा के साथ ही कथा में लुप्त हो जाता है। सभी जगह कृष्ण का पूर्वाभास है यह चरित्र और लेखक ने बड़ी चतुराई से इस चरित्र का चमत्कारी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इस पूरी आत्मकथा में कृष्ण पाठक को अपने जीवन का हिस्सा मानकर साथ-साथ चलते प्रतीत होते है । आश्चर्य की बात ये है की पाठक इन पुस्तकों से ऐसा बंध जाता है की पुस्तक पूरी होने तक उसे हाथ से छोड़ने का मन नहीं होता। मैने स्वयं ने इन 8 पुस्तकों को 20 दिनों में घंटों पढ़ कर पूरा किया क्योंकि जब तक पूरी नहीं हुई सारा ध्यान उसी में लगा रहता था। अद्भुत आश्चर्य यह है कि इस दौरान मन और मस्तिष्क को कुछ भी अन्य विषय में सोचने का अवकाश नहीं रहता। पुस्तक पूरी होने के बाद भी विचारों के मंथन की क्षुधा बढ़ती रही। पाठक बड़ी सहजता से सम्मोहित होकर भगवान कृष्ण और उनसे जुड़े हर पहलू का सूक्ष्म अवलोकन सरलता से करता चला जाता है। मतिष्क के पोषण व विचारों की तृप्ति के लिए पुस्तक संग्रह सर्वश्रेष्ठ है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

राजेंद्र बज

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हौसला सौ गुणा से हजार गुणा तक

कल तक मुझे पता नहीं था कि किसी अपराध में आरोपित होने पर मिल जाने वाली जमानत से हौसला सौ गुणा बढ़ जाता है। लेकिन अब यकीन करना पड़ रहा है कि ऐसा होने पर आदमी किंग से किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है। राजनीति में शहादत देते हुए अमरत्व की ओर बढ़ने की लंबी परंपरा रही है। चतुर सुजान कहते हैं कि आदमी जब किसी चीज का त्याग करता है, तब और अधिक उच्च क्वालिटी की वैकल्पिक चीज उसे सहज ही उपलब्ध हो जाया करती है। जैसे कि चाय छोड़ देने पर दूध का विकल्प सामने परोस दिया जाता है और सांसारिक मोह माया छोड़ देने पर संसार भर की दौलत कदमों में बिछ जाती है। यही नहीं अपितु स्वर्ग में स्थान भी सुरक्षित मान लिया जाता है। खैर।

उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अब मैं भी अपने तमाम उल्टे-सीधे किए-धरे को लेकर कानूनी जंजाल में उलझ जाने पर जमानत हेतु भरपूर प्रयास करूंगा। क्योंकि मुझे अपने हौसले को उनकी तरह सौ गुणा से सीधे हजार गुणा तक करना है। यह मामला तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आम के आम और गुठली के भी भरपूर दाम मिल सकते हो। सोचता हूं सौदा बुरा नहीं है । वैसे भी यदि जो कुछ सहज उपलब्ध है, उसका परित्याग करके जो कुछ दूर की कौड़ी है -या यूं कहे कि दुर्लभ है, एकदम पास आती दिखाई दे, तो यह घाटे का सौदा तो कतई नहीं होगा। मान गए गुरु को, क्या गजब खेल दिखाया है! मैदान में कोई भी खेलें, बाजी तो वही जीतेंगे। इसे कहते हैं चार फेंक कर चालीस पर नजर गढ़ाना। यानी कि लगे तो तीर नहीं तो तुक्का।

वैसे चतुर सुजान यह भी कहते हैं कि आदमी को बड़ी खुशी न मिल सके, तो छोटी-छोटी खुशियों का उत्सव मनाने का प्रयास करना चाहिए। अब उनको ही देखो वह कितने खुश थे, उनके चाहने वालों के तो शायद पैर भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यही नहीं अपितु उनका अंतर्मन झूम-झूम कर खुशी के गीत गाते नहीं थक रहा था। वाकई अंदर रहकर बाहर आने का अपना अलग ही मजा होता है। वैसे तो राजनीति की होली में हर कोई रंगा हुआ है, किसी पर काला-पीला रंग है तो किसी पर चमड़ी से मेल खाने वाला रंग है, जो दिखाई नहीं देता। वैसे जिस पर राजनीति का अच्छा खासा रंग चढ़ गया हो, वह किसी भी रंग से रंगा जाए, लेकिन राजनीति का रंग ही ऐसा रंग होता है जिसके आधार पर दूसरे किसी रंग की परवाह नहीं की जाती।

हमारे इलाके के भैया-दादा भी एक बार धरा गए थे। उन्हें कुछ संघर्ष के बाद जमानत मिल गई थी। लेकिन मुझे मीडिया से यह पता नहीं चल सका था कि जमानत मिलने पर हौसले बुलंद हो जाते हैं। हां इतना जरूर है कि भैया-दादा अब अधिक ट्रेंड हो चुके थे। उनका रुतबा हमारे इलाके में कई गुणा बढ़ गया था। लेकिन मेरी आदत है कि जब तक मीडिया किसी बात को सुर्खियों के साथ प्रकाशित या प्रसारित नहीं करें, कोई भी बात मेरे गले नहीं उतरती । यह अलग बात है कि इधर और उधर दोनों तरफ की बात मीडिया द्वारा करने पर कई अवसरों पर मैं गहरे धर्मसंकट में पड़ जाता हूं। इसलिए केवल और केवल एक ही अखबार पढ़ता हूं और एक ही चैनल पर समाचार देखता हूं। इसके चलते मेरी राजनीतिक धारणा कभी डगमगाती नहीं है।

अभी-अभी चार-पांच दिन पूर्व जो ज्ञान मुझे मिला था, जो कि देश के दिल के तत्कालीन मुखिया के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ था। जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और फिर यह ज्ञान उनके ताजा-ताजा अनुभव पर आधारित था। इसलिए इसका परीक्षण करना समय की बर्बादी के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिन्होंने ऐसा कहा है वह साधारण नहीं असाधारण है। मैं समझता हूं कि जितने भी अपने देश-प्रदेश की राजनीति का कवच धारण किए हुए आरोपितों को जमानत मिली होगी, उन्हें अच्छा खासा अनुभव हुआ होगा कि हौसले बुलंद हो गए हैं। लेकिन डंके की चोट पर किसी ने इस बात को खुलेआम उजागर नहीं किया था। लेकिन उनके लिए तो दो शब्द कहना चाहूंगा कि आप तो आप हैं और आपकी बात ही कुछ और है।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर विशेष

बुजुर्गों के प्रति सम्मान का अभाव और बढ़ती मुश्किलें

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भारतीय संस्कृति में सदा से ही बड़ों के आदर-सम्मान की परम्परा रही है लेकिन आज दुनिया के अन्य देशों सहित हमारे देश में भी वृद्धजनों पर बढ़ते अत्याचारों की खबरें समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। अधिकांश परिवारों में वृद्ध जिस तरह की उपेक्षा झेलने को मजबूर हैं, उससे ज्यादा पीड़ादायक और क्या हो सकता है! समृद्ध परिवार होने के बावजूद घर के बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में जीवनयापन करने को विवश हैं। बहुत से मामलों में बच्चे ही उन्हें बोझ मानकर वृद्धाश्रमों में छोड़ आते देते हैं। हालांकि यह उम्र का ऐसा पड़ाव होता है, जब उन्हें परिजनों के अपनेपन, प्यार और सम्मान की सर्वाधिक जरूरत होती है। एक व्यक्ति जिस घर-परिवार को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है, वृद्धावस्था में जब उसी घर में उसे अवांछित वस्तु के रूप में देखा जाने लगता है तो लगता है जैसे उस घर में रहने वालों की इंसानियत और उनके संस्कार मर चुके हैं।

विश्वभर में ऐसे हालात को देखते हुए ही वृद्धजनों के लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई थी। इसीलिए वर्ष 1982 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 'वृद्धावस्था को सुखी बनाइए' जैसा नारा देते हुए 'सबके लिए स्वास्थ्य' अभियान का शुरू किया था। वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने और वृद्धजनों के प्रति उदारता व उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के अलावा उनकी समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 14 दिसंबर 1990 को निर्णय लिया कि प्रतिवर्ष एक अक्तूबर का दिन दुनियाभर में 'अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की इस पहल के बाद एक अक्तूबर 1991 को पहली बार यह दिवस मनाया गया, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस' के नाम से भी जाना जाता है। बुजुर्गों के प्रति वैसे तो सभी के हृदय में हर पल, हर दिन सम्मान का भाव होना चाहिए लेकिन दिल में छिपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए औपचारिक तौर पर यह दिन निश्चित किया गया। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुरूआत के बाद वर्ष 1999 को पहली बार 'बुजुर्ग वर्ष' के रूप में भी मनाया गया था। इस वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय

वृद्धजन दिवस' 'गरिमा के साथ वृद्धावस्था- दुनियाभर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व' विषय के साथ मनाया जा रहा है। इस विषय के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस का कहना है कि आइए, हम देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हों, जो वृद्धजनों और देखभाल करने वालों की गरिमा का सम्मान करती हों।

भारतीय समाज में सयुंक्त परिवार को हमेशा से अहमियत दी गई है लेकिन आज के बदलते परिवेश में छोटे और एकल परिवार की चाहत में संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म होती जा रही है। यही कारण है कि लोग अपने बुजुर्गों से दूर होते जा रहे हैं और नई पीढ़ी दादा-दादी, नाना-नानी के प्यार से वंचित होती जा रही है। एकल परिवार के बढ़ते चलन के कारण ही परिवारों में बुजुर्गों की उपेक्षा होने लगी है। न चाहते हुए भी बुजुर्ग अकेले रहने को मजबूर हैं। इसका एक गंभीर परिणाम यह देखने को मिला है कि बुजुर्गों के प्रति अपराध भी तेजी से बढ़े हैं। शहरों-महानगरों में आए दिन बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की खबरें दहला देती हैं। दूसरा गंभीर परिणाम यह कि बच्चों को बड़े-बुजुर्गों का सानिध्य नहीं मिलने के कारण उनके जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। एक सर्वे के अनुसार दादा-दादी या नाना-नानी के साथ रहने वाले बच्चों का विकास अकेले रहने वाले बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा और मजबूत होता है और ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास भी अधिक देखने को मिला है। आज पति-पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, ऐसे में बच्चे घर में अकेले रहते हैं और कम उम्र में ही उनमें अवसाद जैसी समस्याएं पनपने लगती हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हालांकि वर्ष 1999 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई थी तथा उससे पहले वर्ष 2007 में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण विधेयक भी संसद में पारित किया गया था, जिसमें माता-पिता के भरण-पोषण, वृद्धाश्रमों की स्थापना, चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रावधान था लेकिन इसके बावजूद देशभर में वृद्धाश्रमों में बढ़ती संख्या इस तथ्य को इंगित करती है कि भारतीय समाज में वृद्धों को उपेक्षित किया जा रहा है। कुछ समय पहले 96 देशों में कराए गए एक सर्वे के बाद 'ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स' जारी किया गया था। उस सूचकांक के मुताबिक करीब 44 फीसदी बुजुर्गों का मानना था कि उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर दुर्व्यवहार किया जाता है जबकि 53 फीसदी बुजुर्गों का कहना था कि समाज उनके साथ भेदभाव करता है।

भारतीय संस्कृति में जन्म देने वाली मां और पालन करने वाले पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। सदियों से मान्यता रही है कि जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान होता है, वे तीर्थस्थल से कम नहीं होते। ऐसे में वृद्धों के उत्पीड़न और उपेक्षा की घटनाएं बढ़ना गंभीर संकट का संकेत है। दरअसल वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन का एक पड़ाव है। यदि आज हम अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं तो आने वाले समय में हमें भी अपने बच्चों से कोई अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। वृद्धावस्था में बुजुर्ग शारीरिक रूप से शिथिल भी हो जाएं तो परिजनों का कर्तव्य है कि पूरे सम्मान के साथ उनका ध्यान रखा जाए। वृद्धावस्था में शारीरिक स्थिति में बदलव आना सामान्य बात है। बुजुर्गों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, याद्दाश्त कमजोर पड़ने, भूलने जैसी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती हैं लेकिन दवाओं के साथ-साथ परिजनों के अच्छे व्यवहार की मदद से ऐसी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

आर्थिक समस्या से जूझते वृद्धों के लिए लगभग सभी पश्चिमी देशों में पर्याप्त पेंशन की व्यवस्था है। भारत में भी वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा है लेकिन उनके सामने स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा अकेलेपन की जो समस्या है, उसका इलाज नहीं है। यह अकेलापन वृद्धजनों को भीतर ही भीतर सालता रहता है। हालांकि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वर्गों के लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वृद्धजनों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। निश्चित रूप से यह कदम वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाएगा और इससे देश में करीब साढ़े चार करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है लेकिन बुजुर्गों के मामले में कई बार चिंताजनक स्थिति यह होती है कि बीमारी के समय में भी सांत्वना देने वाला उनका कोई अपना उनके पास नहीं होता। हालांकि आज कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे वृद्धों के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रही हैं लेकिन ये संस्थाएं भी अपनों की महसूस होती कमी की भरपाई तो नहीं कर सकती। बहरहाल, वृद्धजनों को अपने परिवार में भरपूर मान-सम्मान मिले, इसके लिए सामाजिक जागरूकता जैसी पहल की सख्त दरकार है ताकि वृद्धों के प्रति परिजनों की सोच सकारात्मक होने से बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम जैसे स्थानों की समाज में आवश्यकता ही महसूस नहीं हो।

विचार

झूठ,घृणा और प्रेम

रानी प्रियंका वल्लरी

वरिष्ठ पत्रकार और लेखक

नैतिकता कहती हैं कि प्रेम बुद्धिमानी है,जबकि घृणा मूर्खता है। कमाल यह है तथ्य दोनों का एक ही हैं। अगर मूर्खता का अर्थ कोई अस्तित्व नहीं हो तो बुद्धिमानी का मुल्य कौन ज्ञात करेगा। आप कल्पना कीजिए जो आज आप अपना दिन खुशमय बिताना चाहते तो आपकी चेहरे पर सकारात्मक लकीर खींच जाती है,जिसे आप अपने मन की आँखों से होठों पर भीनी मुस्कान रख देख सकती हैं। ऐसा कर आपको कितनी खुशी मिल सकती है? शायद उसको नापना अपरिमेय हो।

यह सब पाने के लिए जीवन को न्यूटन के प्रथम नियम पर चलना पड़ेगा। जीवन को प्रेम,कर्म के जाल में उलझा कर गतिमान रखना पड़ेगा।

जब कर्म और प्रेम जीवन में तत्पर रहता है तो यकीनन आपको महसूस होगा आप परमानंद की प्राप्ति कर रहें हैं। ऐसा करने से आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे,और आप कार्यशील रहेंगे।आपके अंदर घृणा की प्रवृति जागृत नहीं होगी।

मूर्ख हमेशा आश्वस्त रहता है जबकि विद्वान हमेशा संदेह में जीता है,कहीं गलत साबित ना हो।

जबतक आपकी भाषा में प्रेम नहीं है तब तक आपकी भाषा कमज़ोर रहेगी। प्रेम भरी भाषा मर्यादित होती है यह आक्रोश पैदा नहीं करता। भाषा मृदुल होनी चाहिए।

हम सबने पढ़ा है भाषा वह साधन है। जिसे बोलकर,पढ़कर या लिखकर एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। व्याकरण की भाषा में तीन प्रकार है। मौखिक,लिखित,सांकेतिक।

जबकि निजी और सामाजिक जीवन में भाषा का कई रूप हो जाता है। जैसे (टोन) कहने का लहजा,थोड़ा अलग होता है। सबका अपना थोड़ा अलग अलग सुर। कोई मीठा तो कोई कड़वा ।

किसी के भाषा में संकेत ज़्यादा होता हैं। शारीरिक भाषा जैसे शरीर की मुद्रा,चेहरे की अभिव्यक्ति,इशारों और आँखों की गतिविधि आप तक पहुँचानेझ का काम करता है।आप समझ जाते हैं। कहने वाला व्यक्ति क्या पहुँचाना चाहता हम तक।

भाषा मृदुल होना चाहिए। बड़ी से बड़ी बातें सहजता और विनम्रता के साथ की जाए तो बड़ा से बड़ा युद्ध टाला जा सकता है। भाषा आपकी पहचान है। भाषा से आपकी क्षमता,आपका ज्ञान,आपकी मानसिक स्थिति मिनटों में आपका व्यक्तित्व लोगों के मुठ्ठी में होता हैं।

अच्छी भाषा हमेशा आपको सम्मान और स्नेह दिलायेगा। कबीर दास जी कहते हैं -

ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए
औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए।।

इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे।

जब आपके द्वारा बोली गई भाषा जब दूसरे को सुख पहुँचाती है तो आपको भी आनंद का अनुभव होता है। भाषा का इस्तेमाल सोच समझ और जगह देख कर करनी चाहिए।

झूठ और घृणा आपको वाचाल बनाने का राह बताता है। और अनाप सनाप बकते हैं। जब हम किसी वस्तु या किसी से घृणा करते हैं तो हमारे अंदर यह मनोवृत्ति बसा रहता है। हम दूसरे पर आरोपण कर हम खुद को सिद्ध करते हैं जबकि यह बुराई मुझमें ही है। जिसका हम लोगों को खुद दर्शन कराते हैं।

घृणा या प्रेम का दर्शन करना या कराना आपका अपना व्यक्तित्व होगा।

छल कपट भरे दुनिया में सच बोलना सबसे बड़ा अभिशाप हैं। अमूमन ईमानदार लोग सच सुनने के आदी होते हैं। सच के सामना का जो कड़वां पान का आनंद है वो करेले या किसी आयुर्वेद में आपको नही मिलेगा। किसी से अपने बारे में आपको जानना है तो उसको एक बार बस हल्के से सच का आईना दिखा दीजिए। फिर क्या है आपको वो आपके प्रति जितने भी कड़वाहट मन में भरा हो तनिक समय नही लगेगा सब परोस कर आपके सामने हाज़िर कर देगा।

फिर उठाते रहिए लुत्फ सच बोलने का,सारी खुमारी उतर जाएगी ईमानदारी की कुछ ही क्षण में।

गरुड़ पुराण में वर्णित एक श्लोक हैं -

अकारैरिंगतैगर्त्या चेष्टेया भाषितेन च्।
नेतवक्त्राविकारभ्यां लक्ष्यतेनर्गतः मनः।

अर्थात् जब भी किसी का सच जानना हो तो उसे पूछे नही झूठ है या सच। बस उससे निरंतर बात करते रहिए और उनके शरीर के गतिविधि को भाँपते रहिए सच और झूठ आपको खुद दिखाई दे देगा। मतलब चेहरे के भाव भंगिमा सब आपको प्रदर्शित करता रहता है। शर्त यह है की नज़र आपकी बखूबी बनी रहे।

सच बोलने से घबराइए मत लगातर सत्य बोलते रहिए और लोगों के आंखों के कीड़े बनकर बरकरार रहिए विराजमान रहिए उनके काया में। या तो फिर आपको निकाल कर फेंक देंगे या अपनी आँखों में सजा लेंगे।

मिलावटी दौर और खतरे में जीवन मूल्य

सामयिक

सुसंस्कृति परिहार

लेखक स्तंभकार हैं।

उफ़! मिलावट के दौर का क्या कहना जहां नज़र डालो वहीं इसने अपना अधिकार जमा रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को बढ़त कांग्रेस के माननीयों के यहां जाने के बाद मिली। इसमें संघ का पूरा वजूद भी शामिल है।जांच पड़ताल की जाए तो पता चलेगा कि तमाम आए भ्रष्टाचारियों के दाग़ यहां धुल जाते हैं। वो गंगा की तरह साफ़ है।वैसे भी देश में गंगा पाप धोने वाली नदी के रुप में विख्यात है। जब इस तरह की शानदार व्यवस्था पापियों के लिए मौजूद है तब मिलावट पर कैसी हाय तौबा!

पिछले दिनों तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के प्रसादम लड्डू में मिलावट की चर्चाओं की काफ़ी ज़ोर रहा बहसबाज़ियां होती रहीं। सनातन आस्थावान लोगों की भृकुटी भी तनी दिखी किंतु सब मामला कथित शुद्धता ई से संभल गया।ये भाजपा है इसके पास हर समस्या का हल है। काश.. इसमें कोई मुल्ला होता तो क्या हल्ला इतनी जल्दी थम जाता। जांच पड़ताल कराने से चंद्रबाबू नायडू को कोई फायदा नहीं मिल सका। उल्टा घी में मिलावट के बावजूद अधिक दाम देने पड़ रहे हैं। सोचिए अधिक दाम देने से कभी मिलावट घट सकती है। बल्कि इसका फायदा अन्य मिलावट खोर उठाने बाध्य हो गए जो तेल जैसी अन्य जिंस की मिलावट करते थे वे भी चर्बीवादी हो गए। हाल ही में एक खबर और आ गई कि सलकनपुर मंदिर के प्रसाद में ऐसी मिलावट को लेकर हंगामा हुआ है।वैसे भी घी में तकरीबन 40-50 साल से मिलावट का इतिहास है। तब तेल,डालडा और आलू मिलाया जाता रहा।बाबा रामदेव जी के चैलैंजिंग गाय के घी की असलियत भी सामने आ चुकी है। फिर नंदिनी, सांची, अमूल भला क्यों पीछे रहते। मुनाफ़े के लिए ही तो व्यवसाय किया जाता है।

इसी बीच दवाओं में मिलावट की पोल पट्टी भी खुल गई केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में 53 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय दवाओं का सालाना कारोबार तीन लाख करोड़ रुपए का है। जाहिर है इस कारोबार में बहुत पैसा है यही वजह है कि अधिक मुनाफा कमाने की लालच में नरपिशाचों द्वारा इन दवाओं में मिलावट की जाने लगी हैं और नकली दवाएं भी बनाई जाने लगी हैं। बताया जा रहा है इलेक्टोरल फंड देने वाली कंपनियों ने ना केवल मिलावट का सहारा लिया बल्कि जीवन रक्षक महत्वपूर्ण दवाओं के रेट तिगुने भी कर दिए। आंकड़े बताते हैं कि नामी फार्मा कंपनियों से भाजपा को 61 करोड़, कांग्रेस को 5 करोड़, सपा को 3 करोड़ और आम आदमी पार्टी को 1 करोड़ रुपए के चंदे 'चुनावी बॉन्ड' के जरिए मिले हैं। 'पैन-डी' ने भाजपा को 15 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि तेलंगाना की पार्टी 'बीआरएस' को भी 20 करोड़ रुपए चंदा दिया गया है। प्रख्यात 'सन फार्मा कंपनी' ने भाजपा को 31.5 करोड़ रुपए चंदे में दिए हैं।

यह भी बताया जा रहा है इन 53 दवाओं पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध भी लगा दिया है। लेकिन वे अभी भी धड़ल्ले से बिक रही हैं। आखिर तैयार माल बेचना तो ज़रुरी है। वे आगे मान लीजिए बंद भी हो जाएं तो जो सब्सीट्यूट दवाएं आएंगी क्या गारंटी हैं वो मिलावटी नहीं होंगी। यह तो लगता है सरकार अपनी छवि साफ़ सुथरा बनाने बीच बीच में ये सब करती रहती है।

सवाल यह उठता है कि औषधि मानक नियंत्रण संगठन अब तक कुंभकरणीय नींद में क्यों सोया पड़ा था उसकी नाक के नीचे इतने सालों से ऐसी मिलावटी दवाएं बेची जा रही थी और उसे इनकी जांच की फुरसत ही नहीं मिली थी। अब तो अन्य सभी दवाओं की गुणवत्ता की जांच आवश्यक हो गई है। गौरतलब है कि भारत दवाओं के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा बाजार है। लेकिन औषधि मानक नियंत्रण संगठन ही अगर जांच में सरकार के साथ मिली जुली मिलावट के लिए जिम्मेदार हो तो क्या होंगा?

गंभीर बात तो यह है कि आज तमाम खाद्यान्न और उपभोक्ता सामग्री के साथ ही जीवन मूल्यों पर भी मिलावट इतनी हावी है कि आदमियत ही ख़त्म होती नज़र आ रही है। इसका प्रतिरोध किए बिना ना तो हम अपना जीवन बचा पाएंगे और ना ही जीवन मूल्य। मुनाफाखोर को मुआफ करना उनसे सहयोग लेना ही, इस बीमारी को लाइलाज बना रही है।

दृष्टिकोण

शिक्षा ज्ञान परम्परा पर आधारित हो

डॉ. सौरभ मालवीय

लेखक लखनऊ विवि में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

शिक्षा को लेकर समय-समय पर अनेक प्रश्न उठते रहते हैं जैसे कि शिक्षा पद्धति कैसी होने चाहिए? पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों को पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? वास्तव में स्वतंत्रता से पूर्व देश में अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा पद्धति लागू की। उनका उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य केवल अपने लिए क्लर्क तैयार करना था। देश की स्वतंत्रता के पश्चात स्वदेशी सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता के पश्चात देश में बहुत से कार्य करने थे। संभव है कि इस कारण इस ओर ध्यान नहीं गया हो अथवा उस समय के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ही उचित लगी हो। कारण जो भी रहा हो, देश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से ही पढ़ाई होती रही। कुछ दशकों पूर्व देश में नई शिक्षा पद्धति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी तथा इस पर विचार-विमर्श भी प्रारंभ हुआ।

वर्तमान शिक्षा पद्धति- वर्तमान शिक्षा पद्धति का अपना महत्व है। आज प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे भी विभिन्न विषयों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें आरंभ से ही विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। कुछ दशक पूर्व तक ऐसा नहीं था। किंतु आज की शिक्षा पद्धति में कुछ कमियां भी हैं, जैसे आज परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने पर बल दिया जाता है। अभिभावक भी यही चाहते हैं। उनके लिए इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि उनके बच्चे विषय को समझ कर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अथवा केवल रट्टे लगाकर परीक्षा में उत्तर लिख रहे हैं। उन्हें तो केवल अधिक से अधिक अंक चाहिए। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही योग्य माने जाने लगे हैं। कम या औसत अंक पाने वाले विद्यार्थी कमजोर माने जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बना रहता है। अकसर वे मानसिक तनाव की चपेट में भी आ जाते हैं। दबाव के कारण भी उन्हें अधिक अंक पाने की लालसा रहती है। इसलिए आज शिक्षा व्यवसायिक होती जा रही है। किंतु सुखद बात यह है कि शिक्षाविदों और सरकारों का ध्यान इस ओर गया है तथा इसमें अब परिवर्तन आने लगा है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा दिलाना, इसका एक बड़ा उदाहरण है। अब प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्विद्यालयों तक में मातृभाषा में शिक्षा दिलाई जाने लगी है। आज के समय में हिंदी में चिकित्सीय एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाना किसी स्वप्न से कम नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस बारे में सोचना भी सरल नहीं था। यह एक सार्थक पहल है। भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे।

भारतीय ज्ञान परम्परा- शिक्षा भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित होनी चाहिए। सदैव से हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता विश्व की सर्वाधिक गौरवशाली एवं समृद्ध सभ्यताओं में एक रही है। विश्व के अधिकतर देशों में जब बर्बरता का युग था, उस समय भी हमारी भारतीय सभ्यता अपने शीर्ष पर थी। इसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति की। शिक्षा के कारण ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ। इस पवित्र भारत भूमि पर वेद, पुराणों एवं उपनिषदों की रचना हुई। रामायण की रचना हुई, जिसमें जीवन का सार है। महाभारत की रचना हुई, जो हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा देती है। यह सब शिक्षा के कारण ही संभव हो सका। मानव के लिए जितने आवश्यक वायु, जल एवं भोजन है, उतनी ही आवश्यक शिक्षा भी है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान देने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का भी विकास करे। हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली ऐसी ही थी। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य ही विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण करना होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया गया है, क्योंकि चरित्र के बिना किसी भी गुण का कोई महत्व नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि सभी वेदों का ज्ञाता विद्वान भी सच्चरित्रता के अभाव में श्रेष्ठ नहीं है, किंतु केवल गायित्री मंत्र का ज्ञाता पंडित यदि चरित्रवान है, तो वह श्रेष्ठ है। इससे चरित्र की महत्ता का पता चल जाता है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, अपितु शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ताकि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर सके। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को उसके अधिकारों के साथ-साथ उसके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना भी होना चाहिए, ताकि वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके तथा परिवार एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन कर सके। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन स्तर को उन्नत एवं समृद्ध बनाना भी है। शिक्षा के माध्यम से वह अपने जीवन को सुगम, उन्नत एवं समृद्ध बना सके। प्राचीन काल में विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ व्यवसायिक कार्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे अपने-अपने कार्यों में भी निपुणता प्राप्त कर सकें। एक नैतिकता से परिपूर्ण चरित्रवान व्यक्ति ही अपने कुल, समाज एवं राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विज्ञान पद्धति पर भी आधारित होनी चाहिए तथा इसमें नवाचार भी होना चाहिए।

नैतिक शिक्षा की आवश्यकता- आज के समय में जिस प्रकार समाज में वैमनस्यता तीव्रगति से बढ़ रही है, वह दुख एवं चिंता का विषय है। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन- मूल्यों से विश्वास उठता जा रहा है। वह चरित्र की अपेक्षा धन-संपत्ति को महत्व दे रहा है। इससे उसका नैतिक पतन हो रहा है तथा समाज में अपराध दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज के युवाओं को नित-नई चीजे चाहिए। इसके लिए कुछ युवा अनैतिक कार्यों का सहारा भी लेते हैं। आपराधिक तत्व उनकी महत्वाकांक्षा का अनुचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपराध की दलदल में फंसा देते हैं. इस प्रकार उनका जीवन नष्ट हो जाता है।

इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे मनुष्य का नैतिक विकास हो तथा वह एक सुसभ्य समाज का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हो सके। नई शिक्षा पद्धति में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। नई शिक्षा पद्धति का उद्देश्य ऐसे सदाचारी मनुष्यों का विकास करना है, जिनमें दया, करुणा एवं सहानुभूति आदि गुण हों। जो नैतिक मूल्यों से संपन्न हों, जिनके लिए मानवीय मूल्य सर्वोपरि हों। जो केवल अपने बारे में न सोचकर संपूर्ण समाज के बारे में सोचें। इसलिए उत्तम शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में चारित्रिक विकास एवं मानवीय गुणों को विकसित करने के विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे नागरिक सामाजिक, नैतिकता तथा आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर सकें। हमारे पूर्वजों ने हमें 'वसुधैव कुटुंबकम' का मंत्र प्रदान किया है, जिसका अर्थ है कि धरती ही परिवार है। यही हमारे सनातन धर्म का मूल संस्कार एवं विचारधारा है। हमें इस मंत्र को जीवन में आत्मसात करना होगा। इसका प्रारंभ बाल्यकाल से ही होना चाहिए। यह संस्कार बालकों को घुट्टी में मिलना चाहिए। इसके लिए मूल्य आधारित एवं नैतिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। बच्चों को देश के तीज-त्यौहारों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए। उन्हें इन त्यौहारों से संबंधित देवी-देवताओं की कथाएं सुनानी चाहिए। उन्हें इनसे संबंधी घटनाओं की जानकारी देनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र प्रेरणा का स्रोत है। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता एवं आदर्श मित्र आदि थे। इसके अतिरिक्त देश के महापुरुषों से संबंधित जीवनियां भी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वे इनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि शिक्षा भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित होगी, तो इससे शिक्षकों एवं छात्रों के संबंध और अधिक मधुर होंगे।

साक्षी को मिला गोल्ड मेडल

बैतूल/शाहपुर। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा द्वारा दीक्षांत समारोह में शाहपुर की बेटी साक्षी अजय चंद्रा जगताप कोन्यूट्रीशन एमएससी में सबसे अधिक अंक अर्जित के लिए राज्यपाल

मंगू भाई पटेल द्वारा गोल्ड मेडल और उपाधि की डिग्री दी गई। साक्षी का कहना है कि शिक्षा और पढ़ाई के द्वारा अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। साक्षी जगताप का कहना है, कि वह अच्छी जॉब करके और मानव सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती है। साक्षी की इस उपलब्धि पर उनके परिवारजनों और मित्रगणों द्वारा साक्षी को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है।

आज 1 अक्टूबर को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस के कारण गुल रहेगी बिजली

बैतूल। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल शहर जोन-2 द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को 11 केव्ही टिकारी, 11 केव्ही सदर, 11 केव्ही टाऊन-1 एवं 11 केव्ही टाऊन-2 का मेंटेनेंस कार्य किया जाना है। जिसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। प्रबंधक ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही टिकारी के बच्चा जेल, प्रताप वार्ड, महावीर वार्ड, अखाड़ा चौक, जेरी चौक, गाड़ाघाट पंप, पटने आटा चक्की, नागदेव मंदिर टिकारी, इसाइ चौक, नर्स ट्रेनिंग स्कूल, कृष्णपुरा ठाकरे की चाल, मोती वार्ड, डॉ.कसेरा, गोठी कॉलोनी फांसी खदान से दादावाड़ी, डॉ.पाड़ी गौठाना नाका, शारदा नगर, वैष्णवी नगर, गंगोत्री कॉलोनी, कमानी गेट, थाना चौक, मांग मोहल्ला, दुर्गा वार्ड, गूड़ बाजार, गांधी चौक, साईं मंदिर टिकारी, ग्रीन स्टेट कॉलोनी, भुजलिया घाट आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। प्रबंधक ने बताया कि मंगलवार को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक 11 केव्ही सदर के एमपीईबी कॉलोनी, अग्निहोत्री कॉलोनी, सतपाल आश्रम, प्रताप वार्ड, सुपर किराना, सिंडीकेट बैंक, एसबीआई बैंक, गेंदा चौक, ब्रह्माकुमारी आश्रम, मानस नगर, आईटीआई, एफसीआई गोडाउन, विनायक रेसीडेंसी, द्वारू भट्टी रोड, मिल्क प्लांट, एचएमटी फैक्ट्री आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई प्रभावित रहेगी। इसी तरह 11 केव्ही टाऊन का मेंटेनेंस कार्य के चलते मंगलवार को प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक कोर्ट परिसर, मुल्ला पेट्रोल पंप, पुलिस पेट्रोल पंप, पुलिस कंट्रोल रूम, जिला पंचायत, ट्राईबल कार्यालय, एमपीईबी कार्यालय तथा 11 केव्ही टाऊन-2 के लिंक रोड, चंद्रशेखर वार्ड, कारगिल चौक, बारस्कर कॉलोनी, इंदिरा वार्ड, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी, कोठी बाजार, कंपनी गार्डन, आजाद वार्ड, गर्ल्स कॉलेज, वीवीएम कॉलेज, तलैया मोहल्ला, अंबेडकर चौक, उमप किराना, राठी अस्पताल, ड्रीम होम्स कॉलोनी, नेहरू पार्क, बस स्टैंड, एमजी काम्पलेक्स, लल्ली चौक, सीमेंट रोड आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। प्रबंधक ने बताया कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से समय में बदलाव किया जा सकता है।

गांधी जयंती पर शुष्क दिवस घोषित

बैतूल। जिला आबकारी अधिकारी डॉ.अंशुमन सिंह चढार ने बताया कि कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर बैतूल जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर 2024 को जिले की देशी व विदेशी मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेंगी। जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस 2 अक्टूबर को देशी व विदेशी मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन भी पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

जिला अस्पताल के सब स्टेशन में लगे ट्रांसफार्मर से कॉपर तार और ऑयल चोरी

बैतूल। जिला अस्पताल के सब स्टेशन से अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर में लगा कॉपर तार और ऑयल चोरी कर लिया। घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को अज्ञात चोरों ने अस्पताल के सब स्टेशन के ट्रांसफॉर्मर को खोलकर कॉपर तार और ऑयल चोरी कर लिया है। ट्रांसफॉर्मर में लगे नट-बोल्ट भी चोरी हो गए। चोरी की घटना के बारे में जानकारी तब लगी, जब अस्पताल का इलेक्ट्रिशियन सब स्टेशन पहुंचा था। जिला अस्पताल का यह बिजली सब स्टेशन मर्चुरी के पास बाउंड्रीवाल से लगा हुआ है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अज्ञात चोर बाउंड्रीवाल फांदकर अंदर आये और चोरी को अंजाम दिया। पुलिस अब शहर के सीसीटीवी फुटेच खंगाल कर चोरों की तलाश करेगी। गौरतलब रहे कि अस्पताल में दिन-रात चहल-पहल बनी रहती है। इसके बावजूद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना से ही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद है। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया का कहना है कि अस्पताल परिसर में चोरी होने के संबंध में आवेदन आए है। सीसीटीवी के माध्यम से चोरों की तलाश की जाएगी।

चार महीने से फरार बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बैतूल। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि पिंटू पंडोले नामक व्यक्ति ने उसे बहला-फुसलाकर जबरन दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर, धारा 376, 323, 506 भादवि में विवेचना शुरू की। घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था, और पुलिस उसे पकडने में नाकाम रही थी। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा की, जिससे उसकी तलाश में तेजी लाई गई। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गुजरात में मजदूरी कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम में जगदीश रैकवार, दीपक कटियार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने 28 सितम्बर को गुजरात के मुंद्रा थाना क्षेत्र से आरोपी पिंटू पंडोले 33 वर्ष को हिरासत में लिया और बैतूल लाया। 29 सितम्बर को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में चौकी प्रभारी खेडी, राकेश सरेयाम, जगदीश रैकवार, दीपक कटियार, महेश नगदे, निर्मला का विशेष योगदान रहा।

बैतूल जिले के कई स्थानों पर भूकंप के झटके

संजय द्विवेदी, बैतूल। जिले के कई जगहों पर लोगों ने सोमवार दोपहर भूकंप के झटके महसूस किये। हालांकि भूकंप ज्यादा तीव्र नहीं था, जिससे जानमाल का नुकसान जैसी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन भैंसदेही क्षेत्र में लोगों के घरों में बर्तन की रैक पर रखे बर्तन नीचे गिर गये, दरवाजे हिलने लगे। जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आये। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 1.37 बजे भैंसदेही, बैतूल बाजार और बैतूल शहर के कई हिस्सों में लोगों ने जमीन में कंपन महसूस किया है। खिडकी और दरवाजे हिलने से लोग घरों के बाहर भी निकल आए। जैसे ही धरती में कंपन होने लगा, लोगों को समझने में देर नहीं लगी और लोग घरों से बाहर निकलना शुरु हो गये। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने धरती में कंपन महसूस किया है। कुछ ही सेकंड बाद कंपन बंद हुआ, तो लोगों ने राहत की सांस लीं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.2

की मांपी गई। हालांकि यह मध्यम तीव्रता वाला बताया जा रहा है। भूकंप का केन्द्र बिन्दू काफी दूर था, लेकिन बैतूल मुख्यालय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में इसे महसूस किया गया।

लोगों ने महसूस किये भूकंप के झटके

भूकंप के बाद लोग एक-दूसरे से इसके संबंध में जानकारी लेते रहे। भैंसदेही के कमलेश कावडकर ने बताया कि दोपहर 1.37 बजे अचानक कंपन महसूस होने लगा। कंपन 4 से 5 सेकेंड तक महसूस किया गया। इस दौरान अन्य लोगों ने भी यह कंपन महसूस किया। श्री कावडकर ने बताया कि भैंसदेही के जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस होने पर घरों और ऑफिसों से बाहर आ गये थे। भैंसदेही नप सीएमओ आत्माराम सांवरे ने बताया कि वे उस समय रास्ते में थे। उन्हे भी स्टाफ से कंपन होने की सूचना मिली है।

कहीं भी जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं

बैतूल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप के झटके जरूर महसूस हुए है, लेकिन कहीं भी जान-माल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। भैंसदेही एसडीएम शैलेंद्र हनोतिया ने बताया कि करीब 3 से 4 सेकेंड का कंपन महसूस किया गया है। इससे कोई नुकसान की कोई सूचना नहीं है। वहीं जिला कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि उन्हें भी लोगों से सूचनाएं मिली है कि कंपन हुआ है। वे इस संबंध में सूचना एकत्रित करवा रहे हैं। इधर भूकंप के बाद पूरे जिले में इसकी चर्चा होते रही। लोग बता रहे है कि भूकंप से दरवाजे, बर्तन सहित अन्य चीजों में कंपन और हिलते हुए देखा है।

अटल सेना, अटल नारी शक्ति नॉनवेज होटल के संचालकों से मिली

नवरात्र में नॉनवेज का विक्रय नहीं करने का किया आग्रह

बैतूल। अटल सेना अटल नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने गंज क्षेत्र में नॉनवेज होटल्स में जाकर वहां के संचालकों को नवरात्रि में नॉनवेज के विक्रय ना करने का निवेदन किया। इस संबंध में पिंकी तलमपुरिया ने बताया कि यह नौ दिन आस्था की दृष्टि से हिन्दूओं के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालु प्रातः नंगे पांव मंदिर तक जाकर जल चढ़ाते हैं। कृष्णा नामदेव ने कहा कि हमारे द्वारा संचालकों से आग्रह किया गया कि नॉनवेज बिक्री न करने की दशा में संगठन द्वारा उनका ढोल बाजे के साथ शाल, श्रीफल के साथ सम्मान किया जाएगा। सुनीता राठौर और कीर्ति नामदेव ने कहा कि इस क्षेत्र में प्रमुख मंदिर बड़ी माता मंदिर, बिजासन माता मंदिर, शनि मंदिर, कृष्ण मंदिर आदि हैं। राजेन्द्र सिंह चौहान (केन्डु बाबा) ने कहा कि संचालकों की ओर से बहुत ही सकारात्मक जवाब मिला जिसमें उन्होने कहा कि वे सुबह 9 बजे से पूर्व दुकान नहीं खोलेंगे वहीं कुछ ने कहा कि वे नॉनवेज का विक्रय नहीं करेंगे। इस अवसर पर माधुरी राजूकर नर्मदा शेषकर, गीता वट्टी, सविता, सेवंती साहू, ज्योति पेशवे आदि संगठन की महिलाएं मौजूद थी।

एनयूएलएम के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की ट्रेनिंग

बैतूल। नगर पालिका बैतूल के डे एनयूएलएम शाखा में अमृत टू जीरो योजना अंतर्गत कम्युनिटी बेस वॉटर टेस्टिंग के लिए चयनित डे एनयूएलएम के स्व सहायता का अमित मित्रा के रूप चयन किया गया। चयनित समूह द्वारा नगरीय क्षेत्र के समस्त 33 वार्डों में फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से घरों में जाकर पानी का परीक्षण किया जाना है। इस कार्य हेतु 30 सितंबर सोमवार को डे एनयूएलएम कार्यालय के मीटिंग हाल में एक दिवसीय जल गुणवत्ता परीक्षण आयोजित कर समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। इस संदर्भ में एनयूएलएम के शाखा प्रभारी सिटी मिशन मैनेजर हंसराज मसतकर ने बताया कि ट्रेनिंग उपरांत समूह की महिलाएं शहर के सभी वार्डों में जाकर जल की गुणवत्ता की जांच एफटी के द्वारा करेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में पीएचई विभाग के जिला समन्वय मेनवे एवं जिला लैब टेक्नीशियन निलेश छत्रपाले तथा दिलीप बंजारे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह को एफ टी का वितरण नगर पालिका बैतूल के सीएमओ ओमपाल सिंह भदोरिया और अमृत टू जीरो के नोडल अधिकारी नीरज धुर्वे तथा सिटी मिशन मैनेजर अखिलेश चौहान, सामुदायिक संगठन प्रफुल्ल सिंह, सागर बारस्कर और दीपाली सिन्हा द्वारा वितरित की गई। अमृत टू जीरो योजना के नोडल सिटी मिशन मैनेजर हंसराज मसतकर ने बताया कि इस योजना अंतर्गत कम्यूनिटी की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एनयूएलएम में रजिस्ट्रेशन इस कार्य को करने के इच्छुक है, का किया गया है। सिटी मिशन मैनेजर मसतकर ने बताया कि चयनित समूह नगर के वार्डों में जाकर जल गुणवत्ता की जांच करेगे तथा इस कार्य के लिए अमृत मित्र को प्रति टेस्टिंग शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा।

सड़क सुरक्षा में लापरवाही पर सख्त कदम

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बैतूल। सडक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिले के सभी थाना प्रभारियों द्वारा सड़क किनारे अनधिकृत रूप से खड़े ट्रकों और वाहनों का मेंटेनेंस करने वाले मैकेनिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसके तहत, वायपास क्षेत्र में सडक पर ट्रक खडे कर काम करने वाले मैकेनिकों के टूल्स जब्त किए गए हैं। यह कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई है, जो सार्वजनिक सडक पर वाहन खडा करके और उसकी मरम्मत का कार्य करके सडक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। गौरतलब है कि पूर्व में भी संबंधित मैकेनिकों और वाहन चालकों को सडक सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी और समझाइश दी जा चुकी है। फिर भी, इस प्रकार की गतिविधियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि सडक दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। सडक किनारे वाहनों की मरम्मत करते हुए ट्रक और अन्य भारी वाहन खड़े करने से आम नागरिकों और राहगीरों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इससे सडक पर यातायात बाधित होता है और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ जाती है। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि सडक सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सडक पर यातायात की सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जनता से अपील की जाती है कि सडक सुरक्षा में सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि के बारे में नजदीकी पुलिस थाने में सूचित करें। सडक सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है और इसे सुनिश्चित करने में सभी नागरिकों का योगदान आवश्यक है।

थाना भैंसदेही पुलिस ने गौवंश तस्करी के आरोपियों पर की कार्यवाही

बैतूल। गौवंश तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही जारी है। एसडीओपी भैंसदेही भूपेन्द्र सिंह मौर्य के नेतृत्व में थाना प्रभारी भैंसदेही नीरज पाल और उनकी टीम ने गौवंश तस्करी में संलिप्त आरोपियों पर कार्रवाई की। तीन गौवंश बरामद कर उन्हें गौशाला पहुंचाया गया। अवैध गौवंश तस्करी की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम ग्राम गारपठार आंगनबाडी के पास सडक पर पहुंची। वहां देखा गया कि दो व्यक्ति तीन गौवंश को रस्सी से बांधकर, लकडी से क्रूरता पूर्वक मारते हुए, भूखी-प्यासी हालत में हांकते हुए महाराष्ट्र की ओर ले जा रहे थे। पुलिस को देखकर दोनों व्यक्ति भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड लिया।

नाबालिग बालिकाओं को अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस का नवाचार

बैतूल। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया द्वारा नाबालिक बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नाबालिग बालिकाओं से संबंधित अपराध को रोकने व बालिकाओं को जागरूक करने के लिए जिले के सभी थाना क्षेत्रों में प्रयास-एक कोशिश अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाली एवं ग्रामीण अंचल की किशोरी बालिकाओं को जागरूक करना है, जिससे वे 18 वर्ष से पूर्व किसी भी व्यक्ति द्वारा दिए गए विवाह के प्रलोभन से एव बहला फुसलाकर ले जाने से सतर्क रहे। साथ ही अपने पारिवारिक, सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बने। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल झारिया द्वारा इस अभियान में किशोरियों, बालिकाओं व पुलिस के मध्य संवाद हेतु आशा कार्यकर्ता व आगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दीदी बनाया गया है जो किशोरियों व पुलिस के मध्य संवाद का कार्य करेंगी। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अभियान के तहत 28 सितम्बर को थाना भैंसदेही के सीएम राइज स्कूल, पीएम राइज स्कूल के 700 विद्यार्थियों एवम् शिक्षकों के साथ-साथ, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जिले एवं विकासखंड के सभी बाल संरक्षण अधिकारी, कर्मचारीओ की उपस्थिति मे आज एक विशेष अभियान प्रयास, एक कोशिश के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक बैतूल द्वारा किशोरी बालिकाओं को इस अभियान के उद्देश्यों के बारे में बतलाया गया। साथ ही पॉक्सो कानून व साइबर कानून के बारे में जागरूक किया जाकर अपने साथ घटित किसी भी घटना के संबंध में अपने परिजनों, शिक्षको एवं पुलिस को सूचना दिए जाने हेतु समझाइश दी गई। इस कार्यक्रम में एसडीओपी भैंसदेही भूपेंद्र सिंह मौर्य, एसडीओपी शाहपुर मयंक तिवारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी गौतम अधिकारी, थाना प्रभारी भैसदेही नीरज पाल, प्राचार्य सीएमराइज व एनजीओ के सदस्यगण उपस्थित रहे।

स्वच्छता की पाठशाला, एक साथ 102 स्कूल, 89 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 15 हजार बच्चों ने पढ़ा स्वच्छता का पाठ

संजय द्विवेदी, बैतूल। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सोमवार 30 सितंबर को 102 स्कूल और 89 आंगनवाड़ी केंद्रों में एक साथ स्वच्छता की पाठशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों ने शिक्षक के रूप में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। कार्यक्रम में लगभग 13 हजार बच्चों ने स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया और अपने घर, अपने स्कूल, शहर को स्वच्छ बनाने की शपथ ली। खास बात यह थी कि जिस स्कूल में 28 साल तक केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं बैतूल सांसद दुर्गादास उइके शिक्षक रहे, वहां केंद्रीय राज्यमंत्री ने अपने विद्यार्थियों को उसी अंदाज में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, जैसा पहले इन्हें कभी वे शिक्षक के रूप में पढ़ाते थे।

इन्होंने भी शिक्षक बनकर पढ़ाया स्वच्छता का पाठ- स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्कूलों में आयोजित स्वच्छता की पाठशाला में केन्द्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके के अलावा बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पंवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, एसपी निश्चल एन झारिया, जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, नगर पालिका बैतूल की ब्रांड एम्बेसेडर श्रीमती नेहा गर्ग सहित अन्य क्षेत्रों से अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्षद, अधिवक्ता, डॉक्टर, पत्रकार, समाजसेवियों ने स्कूलों में पहुंचकर शिक्षक बन स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। इस आयोजन में भागीदारी करने वाले जनप्रतिनिधि, अधिकारी, समाजसेवी, डॉक्टर, अधिवक्ता, पत्रकार आदि ने कार्यक्रम की काफी सराहना की। उनका कहना था कि अगर बच्चे स्वच्छता को अपना लेंगे, तो इस शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने में बड़ी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश में करोड़ों शौचालय बनवाये: उइके- केन्द्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके आज सोमवार को शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बैतूल गंज में स्वच्छता का पाठ पढ़ाने पहुंचे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2014 से स्वच्छता का आंदोलन शुरू किया था और आज देश में करोड़ों शौचालय बनवाये जा चुके है, जिसके कारण बाहर खुले में शौच जाना बंद हुआ और हमे गंदगी से मुक्ति मिली। उन्होंने छात्रों से कहा कि स्वच्छता की शुरूआत हमे स्वयं से करनी होगी। इस अवसर पर कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.अनिल सिंह कुशवाह, स्कूल के प्राचार्य श्री लिलहोरे सर सहित अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

घर के कचरे को कचरा वाहन में ही डाले : सीएमओ भदौरिया- पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए बैतूल नपा के सीएमओ ओपी भदौरिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छता को अपने जीवन में उतारे, और घर से निकलने वाले कचरे को नगर पालिका के कचरा वाहन में ही डालें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढने वाले बच्चों को स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण के विषय में भी जानकारियां दी गई। यह इसलिए भी आवश्यक है कि उनमें सीखने और समझने की क्षमता ज्यादा प्रबल होती है, आज स्वच्छता का जो पाठ बच्चों को पढाया गया है, उससे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में एक स्वच्छ, सुंदर और साफ-सुथरे शहर की परिकल्पना साकार हो सकती है।

स्वच्छता को लेकर युवाओं को जागरूक होना होगा

स्वच्छता अभियान चलाया और शपथ ग्रहण की

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस जेएच कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में और परिसर के बाहर स्वच्छता अभियान चलाया साथ ही स्वच्छता की शपथ ग्रहण भी की गई। अभियान एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ.गोपाल प्रसाद साहू और डॉ.शीतल खरे के मार्गदर्शन में अभियान में चलाया गया। इस मौके पर डॉ.जीपी साहू ने कहा कि स्वच्छता को लेकर सभी को जागरूक होना होगा खासतौर पर युवाओं को। डॉ.शीतल खरे ने कहा कि एनएसएस द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में वरिष्ठ स्वयंसेवक हिमांशु पाटिल, अक्षय मालवी, अमित मालवी, कोमल देशमुख, अंजली नागोरे, आयुष घिडोडे, विशाल अमरुते, निकिता सिरसाम, इशियाक अली, पलक राजगौड, नेहा किरोदे, निशा किरोदे, गंगा बुडगरिया, आरती नागले,रिया चौहान ,स्नेहील जायसवाल, किरण धुर्वे, कामिनी, मयंक साहू, दिपाली गायकवाड, आयुष नागोरे,रंजीत कासदे आकाश दुबे, रोहित परते, दयाराम चिचाम,अर्पण पवार आदि का सराहनीय योगदान रहा।

प्राइवेट स्कूल में बच्ची से रेप, पेरेंट्स का हंगामा, चक्काजाम

प्रिंसिपल और स्टाफ को पीछे के गेट से निकाला, स्कूल सील किया

रतलाम (नप्र)। रतलाम में प्राइवेट स्कूल में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। सोमवार सुबह पेरेंट्स इकट्ठा होकर स्कूल पहुंच गए। यहां स्कूल के बाहर डायरेक्टर और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। चक्काजाम कर सड़क पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी करवा दी। स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ को पीछे के गेट से सुरक्षित निकाल दिया। प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर पेरेंट्स माने।

10वीं के छात्र ने किया था रेप

एक प्राइवेट स्कूल में रविवार को 5 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया था। बच्ची यूकेजी में पढ़ती है। आरोपी स्कूल के चौकीदार का बेटा है। वह स्कूल की दूसरी ब्रांच में 10वीं का छात्र है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया था।

हिंदू संगठनों के साथ पहुंचे परिजन

रोजाना की तरह स्कूल सुबह खुला। करीब 9.30 बजे के बाद हिंदू संगठन पदाधिकारी, पेरेंट्स स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। धीरे-धीरे और पेरेंट्स भी स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना पर एसडीएम अनिल भाना, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, सीएसपी अभिनव बारंगे, आईए थाना प्रभारी वीडी जोशी बल के साथ पहुंच गए। अफसरों ने पेरेंट्स से चर्चा की, लेकिन वे

मानने को तैयार नहीं थे। स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल व क्लास टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पेरेंट्स का कहना था कि एक बार इनको सामने लाओ। प्रदर्शन के दौरान पेरेंट्स सड़क पर बैठक गए। यहां स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी की।

स्कूल की करना पड़ी छुट्टी

कुछ देर बाद पेरेंट्स स्कूल के बाहर जाकर सड़क पर बैठ गए। हंगामा बढ़ता देख बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पहले स्कूल की छुट्टी करवाई। पीछे के रास्ते से बच्चों को पेरेंट्स के साथ रवाना किया। हंगामा देख बच्चे भी डर गए। छोटे बच्चे तो रोने लगे। एसडीएम व सीएसपी ने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की। मौके पर छोटा वज्र वाहन, शहर के सभी थाना प्रभारी समेत पुलिस बल तैनात कर दिया गया। नगर निगम से फॉयर लॉरी भी मंगवा ली।

कुर्सी पर खड़े होकर समझाती रहीं प्रिंसिपल: इस बीच कुछ पेरेंट्स ऑफिस में घुस गए। यहां मौजूद स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल को घेर लिया। पेरेंट्स पूछने लगे कि बच्चियां आएंगी, तो स्कूल में क्या सुरक्षा दी जाएगी? आप गारंटी लेते हो? स्कूल में ऊपरी मंजिल पर सीसीटीवी क्यों नहीं है? जिस बच्ची के साथ घटना हुई, उसके भी परिजन पहुंचे। पेरेंट्स का कहना था कि पूरे स्कूल परिसर में सीसीटीवी लगाए जाएं। हमें भी उसकी आईडी दी जाए, ताकि हम बच्चों को देख सकें। स्कूल प्रिंसिपल को कुर्सी पर खड़े होकर पेरेंट्स को समझाना पड़ा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।

पीछे के रास्ते से स्टाफ को निकाला

अफसर पीछे के रास्ते से स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल समेत स्टाफ को बाहर निकालने के लिए ले गए। इधर, भीड़ भी स्कूल के पीछे गेट की तरफ खड़ी हो गई। नारेबाजी करने लगी। सभी को अलग से रूम में बैठाया। बच्चों की छुट्टी कर एक-एक रूम में जाकर देखा कि कोई बच्चा तो नहीं रहा। फिर बाद में प्रिंसिपल, डायरेक्टर व अन्य स्टाफ को निकाल कर स्कूल खाली करवाया।

एडीएम व एएसपी ने स्कूल करवाया सील

अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एएसपी राकेश खाखा भी मौके पर पहुंचे। अफसरों ने कुर्सी पर खड़े होकर माइक थामा। आश्वासन दिया कि लिखित शिकायत दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। सभी को थाने या एसपी ऑफिस बुलाया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है घटना में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है। जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों से भी अपनी मांग, शिकायत का स्टेटमेंट देने के लिए कहा है, ताकि कार्रवाई की जा सके। राकेश खाखा, एएसपी

सुरक्षा इंतजाम के बाद खुलेगा स्कूल-एडीएम: एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि घटना को लेकर आक्रोश था। पेरेंट्स का कहना था कि जब तक सुरक्षा के इंतजाम न हों, स्कूल बंद रखा जाए। अभी ताला लगाया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर श्री कंग ने की भेंट

- ब्रिटेन और प्रदेश के बीच व्यापार तथा निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर हुई चर्चा

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर श्री हरजिंदर कंग ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट कर मध्यप्रदेश से ब्रिटेन को निर्यात और प्रदेश में निवेश बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश, ब्रिटेन को प्र-संस्कृत खाद्य पदार्थों और कृषि उत्पादों का महत्वपूर्ण निर्यातक है। मध्यप्रदेश से कपड़ें व तैयार वस्त्रों, फार्मास्यूटिकल्स और प्लास्टिक उत्पादों व पैकेजिंग सामग्री का भी निर्यात किया जाता है। चर्चा में निर्यात को बढ़ाने तथा प्रदेश में आईटी, खाद्य प्र-संस्करण, परिधान, ऑटोमोबाईल, स्वास्थ्य, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भोपाल में आगामी 7-8 फरवरी 2025 को होने जा रही इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर श्री कंग को आमंत्रित भी किया।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर श्री सिंह ने खरीदी कार्य तथा खाद्य उपलब्धता के संबंध में दिए निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने उपार्जन और खाद्य आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में ऑनलाइन स्टॉक को अपडेट रखने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने इस कार्य के लिए गूगल सीट तैयार कराई जाकर ऑनलाइन सिस्टम जनरेट करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें किसानों को वितरित किए जाने वाले यूरिया और डीएपी की जानकारी दर्ज हो सके।कलेक्टर श्री सिंह ने खाद की कालाबाजारी की रोकथाम के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि खरीदी केन्द्रों की तैयारी कर लें पिछली बार जिन खरीदी केन्द्रों पर समस्या उत्पन्न हुई थीं। उनकी सूची तैयार कर उन खरीदी केन्द्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाएं, ताकि खरीदी कार्य के दौरान कृषक बांधों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कृषक बंधुओं की सुविधा की दृष्टि से अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधितों को दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएमो को भी निर्देशित किया है कि खाद वितरण कार्य जिले की 154 सोसायटियों पर होना है। इस हेतु नजर बनाए रखे, ऑन लाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि खाद की काला बाजारी ना हो। शासन की मंशा है कि प्रत्येक किसान को यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। इस हेतु बेहतर व्यवस्थाएं क्रियान्वित करें। इसके अलावा उन्होंने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के प्रचार-प्रसार कार्यो पर भी बल दिया है।

स्वच्छता की प्रेरणा दे रहे कार्यालय

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति की विशेष पहल की जा रही है। शासकीय अवकाशों में भी कार्यालयों को खोल कर साफ सफाई के कार्यो को पूरा किया जा रहा है। शासकीय कार्यो को संपादित करने वाले विभाग कार्यालयों से आमजनों को स्वच्छता की प्रेरणा मिल रही है। कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों के हाथों में झाड़ू पौछा के कपड़े देख कर आश्चर्यचकित न हो। गांधी जयंती दो अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक अपनी दैनंदिन का हिस्सा बना कर जीवन में स्वच्छता के दामन को पकड़ कर रखें, अस्वच्छता से अनेक प्रकार की तकलीफों से बचा जा सकता है। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देश का पालन करते हुए हरेक विभाग स्वच्छता कार्य को टीम वर्क की भावना से कर रहे हैं। शनिवार को जिला जेल, कलेक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों के साथ साथ शैक्षणिक संस्थानों में एक साथ सफाई कार्य किए जा रहे हैं।

आजीविका मिशन में सामान्य सभा का आयोजन हुआ

सिवनी मालवा। आजीविका मिशन द्वारा जनपद पंचायत सभा कक्ष में वार्षिक सामान्य सभा का आयोजन हुआ। जनपद पंचायत अध्यक्ष रेणुका मृगेंद्र मंडलोई की अध्यक्षता में किया गया। थाना प्रभारी उषा मरावी, आजीविका मिशन जिला कार्यालय से सुरेखा की उपस्थिति में 37 ग्रामों के ग्राम संगठन एवं स्व सहायता समूहों की 350 महिलाएं उपस्थित हुई। बैठक में आजीविका मिशन एवं समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए प्रगति एवं उपलब्धियों को बताया। समूह और मिशन के सहयोग से लखपति बनी दीदियों द्वारा अपनी सफलता की कहानियां सुनाई गई।

झाड़ू लगाकर एवं कचरा उठाकर सफाई संदेशों का संप्रेषण

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा

विदिशा (निप्र)।स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता थीम पर कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा स्वयं श्रमदान करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर एवं अन्य क्षेत्रों में संचालित शासकीय कार्यालयों में विभिन्न स्थानों पर झाड़ू लगाकर एवं कचरा उठाकर सफाई की जा रही है। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह

समीक्षात्मक बैठकों में अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सफाई को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करे, प्रतिदिन अपने घर एवं घर के आसपास सफाई रखने हेतु श्रमदान करें तथा अन्य व्यक्तियों को भी स्वच्छता का वातावरण निर्मित करने हेतु प्रेरित करें। कलेक्टर श्री सिंह की पहल पर सभी शासकीय कार्यालयों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन परिसर में झाड़ू लगाकर एवं कचरा उठाकर सफाई की जा रही है। शासकीय सेवकों द्वार कार्यालय परिसर में संयुक्त श्रमदान कर जिले के नागरिकों को अपने घर एवं घर के आसपास तथा सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई बनाए रखने संदेश दिया जा रहा है।

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जिलेभर में अनेक स्वच्छता गतिविधियां आयोजित

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जिले में 17 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जिले भर में अनेक स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिले स्वच्छता जागरूकता रैली, स्वच्छता की शपथ, रंगोली, स्वच्छता गायन, स्वच्छता भजन, स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जा रही है। यह गतिविधियां 02 अक्टूबर तक चलेगी। पखवाड़ा के तहत बुदनी के ग्राम नीनौर में स्वच्छता मित्रों को सुरक्षा कल्याण शिविर में शॉल, तोलिया देकर सम्मानित किया गया एवं स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया। इसी प्रकार बुदनी के ग्राम जोनतला में स्वच्छता मित्रों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

शांति समिति की बैठक 01 अक्टूबर को आयोजित

सीहोर (निप्र)।कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशानुसार नवरात्रारम्भ, विजयादशमी, वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस डे, मकर संक्रांति आदि त्योहारों को शान्ति पूर्वक मनाये जाने के लिए 01 अक्टूबर 2024 को शाम 04:30 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में शान्ति समिति की बैठक आयोजित की गई है।

जनसुनवाई से मिला भूमि पर कब्जा

विदिशा (निप्र)। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम के प्रति आवेदकों का विश्वास पहले से कई गुना अधिक बढ़ रहा है। वह भी क्यों ना हो, उनकी मूलभूत व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं का निदान अविलंब हो रहा है।

जनसुनवाई कक्ष में ही अनेक आवेदकों की समस्यायों का समाधान हो जा रहा है, ऐसी समस्याएं जो कक्ष के बाहर संभव हैं, उनका निदान आगामी जनसुनवाई के पहले कराया जाने की प्रक्रिया का सफलता पूर्वक विभागीय अधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। जनसुनवाई कार्यक्रम अब आवेदकों के लिए वरदान साबित हो रहा है उनकी जमीन संबंधी समस्याएं भी चंद दिनों में हल हो रही हैं। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह को शमशाबाद तहसील के ग्राम हीरापुर के कृषक आवेदक श्री लच्छू राम पुत्र मुल्ला अहिरवार ने अपनी व्यथा सुनाते हुए आवेदन दिया। वस्तु स्थिति को भांपते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गौरतलब हो कि आवेदक की भूमि

सर्वे क्रमांक 333/2 रकबा 0.932 हे. में पूर्व में सोयाबीन की बोनी के समय लगभग जून जुलाई में अंतर्गत कब्जा दिया जा चुका है लेकिन आशाराम मुंशीलाल मैना द्वारा दादागिरी से पुनः कब्जा ले लिया था। अतिक्रमणकर्ता आशाराम उक्त भूमि पर लगभग 15 से 20 वर्षो से कब्जा किए हुए था। एसडीएम ने के आदेश के पालन में रविवार 29 सितंबर को आशाराम को बेदखली की कार्यवाही कर लच्छूराम को कृषि भूमि पर कब्जा सौपा गया है और अतिक्रमणकारी के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने के कार्य पूर्ण हुए हैं। लक्ष्मी राम अहिरवार का कहना है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी जमीन पर मुझे कब्जा मिल जाएगा प्रशासन की ऐसी पहल से सभी हैरान -परेशान गरीबों को समय पर न्याय व विश्वास का पैगाम चहुंओर बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को किया जाएगा लाभान्वित : केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान

सीहोर (निप्र)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इछावर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश में निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेक परिवारों के पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। जो पात्र लोग इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं, उनको इस योजना से लाभन्वित करने के लिए नया सर्वे शुरू किया जाएगा और वंचित लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और किसान उसकी आत्मा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

केन्द्रीय दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित

विदिशा (निप्र)। केन्द्रीय दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना तहत वर्ष 2024-25 के लिये संबंधित विद्यार्थियों हेतु प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर 30 जून 2024 से दाखिल किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की सेवाएं अब कॉमन सर्विस सेंटर पर भी उपलब्ध हैं। आवेदक अपने नजदीकी सीएससी पर जाकर छात्रवृत्ति योजना से जुडी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन के लिए पूरी गतिविधि (संदर्भ संख्या का निर्माण, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, वन-टाइम पंजीकरण संख्या का निर्माण और आवेदक का पूरा आवेदन पत्र ऑनलाईन करने) के लिए कुल शुल्क 30.00 रूपयेतय किया है।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में शामिल हैं सीहोर जिले के 80 गांव

सीहोर (निप्र)। देश के जनजाति बाहुल्य गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा- 56,333 करोड़ रुपये और राज्य हिस्सा- 22,823 करोड़ रुपये) के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को शुरू किया गया है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान में सीहोर जिले के जनजाति बाहुल्य 80 ग्राम शामिल हैं।

सीहोर जिले के जनजाति बाहुल्य ग्राम

जिले के जनजातीय बहुल्य गांवों में रतनखेड़ी, बील खेड़ा खुर्द, अमामय, सालीखेड़ा, रबियाबाद, आवली खेड़ा, नारपा खेड़ी, पीथपुरा, श्यामपुरा मगरदा, कुडीखाल, ललिया खेड़ी, झरखेड़ा, गडिया, बोरपानी अलियस, दूदालावा, जामली, सुवाखेड़ा, मोया पानी, अलीपुर, नादान, वीरपुरा, पांगिया, धनखेड़ा, रामगढ़, सोहनखेड़ा, बावडिया चौर अलियस शहर, बलोंदिया, नवलपुरा, बामला दाद, अबिदाबाद, खामखेड़ा, लोटिया, चिकलपानी, झालपिपली, सरस, लोहा पठार, सेवनिया परिहार, मगरपथ, ढ़ोंगलपानी, इटावा खुर्द, पिपलानी, किशनपुर, घुटवानी, हामिदगंज, बोरखेड़ा खुर्द, मंजीखेड़ी, बसंतपुर पांगरी, छापरी, कुरी नायापुरा, सनकोटा, कोसमी, रीकगंज, हबीब नगर, सिंहपुर, नलगांव, मोगरा खेड़ा, भिलाई, मरियादोह, पलासी कला, गिल्लौर, सेवनिया, आमाझिर, पाटतलाई, अमीरगंज, लावापानी, कोटरा पिपरिया, छतरकोटा, अमदो, खजूरी, ढ़ाबा, भीलपाटी, नरेला, चिचाहाखुर्द, झोलीपुर, खानपुरा, रतनपुर, कोसमी, मथर, खंदावद, देवगांव, खाटपुरा शामिल हैं।

पूरे देश में लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिससे 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल 549 जिले और 2,740 ब्लॉक के गांव शामिल होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10.45 करोड़ है और देश भर में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं, जो दूरदराज और पहुंच से दूर क्षेत्रों में रहते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना और पीएम जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) की सीख और सफलता के आधार पर जनजातीय क्षेत्रों एवं समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करना है। इस मिशन में 25 कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत उन्हें आवंटित धनराशि के माध्यम से अगले 5 वर्षों में समयबद्ध तरीके से इससे संबंधित योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके

लक्ष्य-1. सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास : पात्र परिवारों के लिए पक्का घर और अन्य सुविधाएं- पात्र अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों को पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत नल के पानी (जल जीवन मिशन) और बिजली आपूर्ति (आरडीएसएस) की उपलब्धता के साथ पक्के आवास मिलेंगे। पात्र एसटी परिवारों की आयुष्मान भारत कार्ड (पीएमजेएवाई) तक भी पहुंच होगी।

गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार

एसटी बहुल गांवों (पीएमजीएसवाई) के लिए सभी मौसम में बेहतर सड़क संपर्क, मोबाइल कनेक्टिविटी (भारत नेट) और इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करना, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा (एनएचएम, समग्र शिक्षा और पोषण) सुनिश्चित करना।

लक्ष्य-2 आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना : क कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देना और आजीविका (स्वरोजगार) में सुधार करना- प्रशिक्षण (कौशल भारत मिशन/जेएसएस) तक पहुंच प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि एसटी समुदाय के छात्र/छात्राएं हर साल 10वीं/12वीं कक्षा के बाद दीर्घकालिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त करें। इसके अलावा, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी) के माध्यम से विपणन सहायता, पर्यटक गृह प्रवास, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के माध्यम से एफआरए पट्टा धारकों को सहायता प्रदान करना।

लक्ष्य-3- सभी की अच्छी शिक्षा तक पहुंच: शिक्षा- स्कूल और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाना और जिला/ब्लॉक स्तर पर स्कूलों में जनजातीय छात्रावासों की स्थापना करके एसटी छात्रों (समग्र शिक्षा अभियान) के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सस्ती और सुलभ बनाना।

राइट क्लिक

तिरूपति प्रसादम् कांड से उठे धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक सवाल

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के वरिष्ठ संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

हिंदुओं के प्रसिद्ध तीर्थ तिरूपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी की मिलावट का सनसनीखेज मामला उजागर कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर हमला कर तगड़ा राजनीतिक निशाना भले साधा हो, लेकिन इस समूची घटना में हिंदू मंदिरों में बनने, भगवान को चढ़ने और मंदिरों के बाहर दुकानों में बिकने वाले प्रसाद की प्रामाणिकता पर ही प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। तिरूपति मामला सामने आने के बाद देश के कई बड़े मंदिरों ने अपने यहां बनने वाले प्रसाद की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच करानी शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ मंदिरों के बाहर दुकानों में बिकने वाले प्रसाद की शुद्धता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है लोग भगवान को प्रसाद के रूप में केवल फल व मेवे ही चढ़ाएं। इस पूरे मामले पर हिंदू समाज में खलबली है। संदेश यह जा रहा है कि लोगों ने भगवान के प्रसाद को भी नहीं छोड़ा। साथ ही प्रसाद की शुद्धता के मापदंड तय करने तथा सभी हिंदू मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज के हाथों में सौंपने व सनातन धर्म रक्षा बोर्ड बनाने जैसी मांग भी उठने लगी है। विश्व हिंदू परिषद के डॉ. सुरेंद्र जैन ने तिरुपति लड्डू मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। साथ ही उन्होंने हिंदू मंदिरों के समाजीकरण की मांग भी की है।

इस गंभीर मुद्दे के तीन अहम पहलू हैं, पहला तो धार्मिक है। हिंदू मंदिरों में बनने और चढ़ने वाले प्रसाद की शुद्धता और प्रामाणिकता को लेकर हिंदू धर्म में न तो स्पष्ट गाइड लाइन है और न ही कोई निश्चित मापदंड। मोटे तौर पर सभी इस बात पर एकमत है कि भगवान का प्रसाद शुद्ध शाकाहारी हो (इसमें केवल गुवाहाटी का कामाख्या देवी मंदिर अपवाद है, जहां शाकाहारी नैवेद्य के साथ मांसाहारी (मछलीयुक्त) प्रसाद का भी भोग लगता है और जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई) तथा मीठा हो। देवता मीठा ही पसंद करते हैं, क्योंकि मीठा प्रसन्नता का परिचायक है। हालांकि हिंदू धर्म में 'एक देवता, एक प्रसाद' जैसा कोई फार्मूला लागू नहीं है। हर देवता को अलग (भक्तों की भावना और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार) प्रसाद चढ़ता है। मसलन भगवान विष्णु को खीर अथवा सूजी का हलवा,शिव को पंचामृत तो कुछ जगह भांग का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है, देवी सरस्वती को दूध पंचामृत, तिल के लड्डू, देवी दुर्गा को खीर, मालपुए, फल, गणेशजी को मोदक अथवा लड्डू, भगवान राम को केसर भात,गुड़ से बने लड्डू, हनुमानजी को पंच मेवा, लड्डू, श्रीकृष्ण को माखन मिश्री, काल भैरव को मदिरा का भोग लगता है।

जहां तक मंदिरों में बनने वाले प्रसाद की बात है तो देश में कुछ बड़े मंदिर ही हैं, जिनमें प्रसाद बनता है और भक्तों को बांटा जाता है। ऐसे मंदिरों की संख्या दो दर्जन तक हो सकती है। बाकी मंदिरों में भक्त खुद ही बाजार से प्रसाद लाते हैं, और उसे मंदिर में चढ़ाते है। हालांकि मंदिरों में प्रसाद, फल फूल नारियल आदि की बिक्री और खपत का अलग अर्थशास्त्र है और यह हजारों लोगों को रोजगार भी देता है। बॉम्बे आईआईटी के पूर्व छात्रों द्वारा किए एक सर्वे में बताया गया कि भारत में कुल 7 लाख मंदिर हैं। जबकि एक वेबसाइट ट्रैवल ट्राइंगल के मुताबिक भारत में मंदिरों की कुल संख्या 20 लाख तक हो सकती है। इसे सही माने तो भारत में मंदिरों के प्रसाद का कारोबार हजारों करोड़ रू. का है।

दूसरा मुद्दा नैतिक है। तिरूपति मंदिर सैंकड़ों सालों से भक्तों की आस्था का केन्द्र रहा है। प्रतिदिन हजारों भक्त यहां आते हैं। लिहाजा प्रसाद की आवश्यकता भी उसी अनुपात में होती है। यही कारण है कि तिरूपति तिरूमाला देवस्थानम् (टीटीडी) ट्रस्ट खुद प्रसाद बनवाता और वितरित करता है। रोजाना औसतन यहां साढ़े 3 लाख प्रसाद के लड्डू तैयार होते हैं। प्रत्येक लड्डू की कीमत 50 रू. होती है। इसमें हर दर्शनार्थी को प्रसाद के रूप में मुफ्त दिया जाने वाला लड्डू छोड़ दें तो करीब 3 लाख लड्डू रोजाना बिकते हैं। इसका मूल्य करीब 1.5 करोड़ रू. प्रतिदिन होता है। यानी कि सालाना 548 करोड़ रू.। आधिकारिक जानकारी के अनुसार तिरूपति मंदिर को लड्डू बनाने सालाना 2800 टन घी की जरूरत होती है।। 320 रू. प्रति किलो के थोक भाव से यह राशि करीब 832 करोड़ रू होती है। जो घी के बाजार भाव के हिसाब से लगभग 800 करोड़ रू. कम है। इसमें लड्डू बिकने की औसतन 5 सौ करोड़ की राशि कम कर दें तो बाजार भाव के हिसाब से मंदिर को मात्र 300 करोड़ रू. सालाना की बचत होती। तो क्या 800 करोड़ रू. बचाने के लिए मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया? जबकि मंदिर को हर साल 1500 करोड़ रू. का चढ़ावा मिलता है।

यह पूरा घोटाला उजागर होने के बाद आंध्र सरकार ने असली घी सप्लाई का ठेका फिर से कर्नाटक की दुग्ध सहकारी संघ को दे दिया है, जिसने 475 रू. प्रति किलो से कम में घी सप्लाई करने से मना कर दिया था और प्रसाद मिलावट कांड के पहले भी वही सप्लाई कर रहा था। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप था कि पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान तिरूपति में प्रसादम् बनाने के लिए मात्र 320 रू. प्रति किलो के भाव से घी सप्लाई करने वाली तमिलनाडु की डेयरी कंपनी एआर डेयरी प्रॉडक्टस को ठेका दिया गया। गड़बड़ी की शिकायत के बाद कंपनी द्वारा सप्लाई किया जाने वाला घी एनडीडीबी की लैब में घटिया पाया गया और इसमे मछली का तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट मिली। भगवान के प्रसाद में इस्तेमाल घी में ऐसी मिलावट महापाप है और भगवान और भक्तों की आस्था के साथ धोखा है। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। यहां बड़ा सवाल यह है कि आज बाजार में शुद्ध घी 5 सौ रू. किलो से कम में कहीं भी उपलब्ध नहीं है तो फिर एआर डेयरी 320 रू. प्रति किलो में शुद्ध घी सप्लाई किस आधार पर कर रही थी, वह भी कंपनी का मुनाफा और परिवहन खर्च जोड़कर। दूसरे, इतने कम रेट पर टेंडर जाने पर तिरूपति प्रबंधन को शक क्यों नहीं हुआ? यह शंका तब भी क्यों नहीं उठी जब एआर डेयरी द्वारा घटिया घी की सप्लाई शुरू हुई और उसका इस्तेमाल प्रसाद बनाने में होने लगा? अगर घी के नाम पर मछली का तेल मिलाया गया था तो उसकी बदबू तो तुरंत ही आ जाती है। उस वक्त प्रसाद बनाने वाले तिरूपति के ब्राह्मण क्या कर रहे थे? सरकार बदलने पर ही यह मुद्दा जोर शोर से क्यों उठा?

यहां असल मुद्दा नैतिकता और नीयत का है। अगर मंदिर के कर्ताधर्ता ही मिले हुए हों तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आप सरकार से लेकर समाज के हाथ में भी मंदिर का प्रबंधन दे देंगे और नीयत शुद्ध नहीं रही तो भ्रष्टाचार बंद होने वाला नहीं है। सवाल यह भी है कि हिंदू मंदिरों को सरकार नियंत्रित ट्रस्टों के हाथों में देने की नौबत क्यों आई? इसका मुख्य कारण भी कुप्रबंधन और पंडे पुजारियों का भ्रष्टाचार रहा है। अभी भी अधिकांश मंदिरों में चढ़ावे की रसीद कटाने के बाद भी पंडे पुजारी भक्तों से 'दान' की अपेक्षा रखते ही हैं। कई बार तो इसके लिए जोर जबरदस्ती भी की जाती है। श्राद्ध कर्म वाले स्थानों पर तो यह शोषण बेशर्मी की हद तक है। इस पर कैसे और कौन रोक लगाएगा? भगवान के हर काम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ-साथ अंतःकरण की पवित्रता का आग्रह भी क्यों नहीं हो चाहिए?

चौथे, क्या अब मंदिर प्रसाद की शुद्धता के लिए भी एफएफएसएआई कोई मानक और उनका कड़ाई से पालन तय करेगा? या फिर खुद हिंदू समुदाय ही इसकी पहल करेगा? काशी विद्वत परिषद ने कहा है कि वह और अखिल भारतीय संत समिति मिलकर देश के सभी बड़े मंदिरों के प्रबंधक और व्यवस्थापकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद प्रसाद के बारे में नई व्यवस्था लागू करने के निर्णय सरकार को अवगत कराया जाएगा।

तिरूपति प्रसादम् कांड का दूसरा पक्ष राजनीतिक है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने तिरूपति प्रसादम् की पवित्रता के सवाल पर विरोधी जगन मोहन रेड्डी को घेर कर खुद को बड़ा हिंदू हितैषी साबित करने की कोशिश की है। यानी वे हिंदुत्ववादी भाजपा को आंध्र में पैर पसारने पर अभी से ब्रेक लगाना चाहते हैं। नायडू की रणनीति बहुत साफ है, एक तरफ वह खुद को कट्टर हिंदू के रूप में पेश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राज्य में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण भी दे रहे हैं और सरकार में शामिल भाजपा चुप है। बहरहाल प्रसादम् कांड ने मंदिरों में प्रसाद की पवित्रता और मानकीकरण की बहस छेड़ दी है। इसका कोई सकारात्मक हल निकले तो अच्छा ही है।

भोपाल में 16 किसान संगठनों का प्रदर्शन

बेड़ियां डालकर पहुंचे किसान नेता; बोले- सरकार हमारी नहीं, पूंजीपतियों की सुन रही

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में किसान सोयाबीन के दाम 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल किए जाने को लेकर पिछले एक महीने से आंदोलित हैं। सोमवार को भोपाल में प्रदेश के करीब 16 किसान संगठन नीलम पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। सोयाबीन, गेहूं, चना, मक्का सहित तमाम फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने जैसी तमाम मांगों को पूरा करने के लिए डटे हैं।

बेड़ियां डालकर पहुंचे किसान नेता

प्रदर्शन में शामिल होने कटनी के किसान नेता एके खान हाथ-पैरों में लोहे की बेड़ियां डालकर पहुंचे। किसान नेता एके खान का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार सुन नहीं रही है, बल्कि सरकार पूंजीपतियों के हिसाब से फैसले ले रही है। हमारी मांग है कि सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चना सहित तमाम फसलों की एमएसपी किसानों की लागत के हिसाब से तय हो और एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए।

ये हैं किसान संगठनों की मांगें

- समर्थन मूल्य (सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूला) पर खरीद की कानूनी गारंटी
- किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्ति
- सोयाबीन की एमएसपी 8000 रुपए प्रति क्विंटल
- धान एमएसपी 5000 रुपए प्रति क्विंटल
- मक्का एमएसपी 3000 रुपए प्रति क्विंटल
- गेहूं एमएसपी 4000 रुपए प्रति क्विंटल
- कपास एमएसपी 10,000 रुपए प्रति क्विंटल
- चना एमएसपी 8000 रुपए प्रति क्विंटल
- गन्ने एमएसपी 500 रुपए प्रति क्विंटल
- अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराकर राजस्व मुआवजा और फसल बीमा का भुगतान किया जाए।
- प्राकृतिक आपदा, सर्प दंश, बिजली का करंट तथा जंगली जानवर के हमले से मौत होने पर पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।
- वन अधिकार के पट्टाधारी किसानों को कब्जा दिलाया जाए।
- चरनोई और तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।
- बिजली बिल माफ किया जाए।
- आवारा पशुओं तथा जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हुए नुकसान पर लागत से डेढ़ गुना मुआवजा दिया जाए।
- गेहूं-चावल के साथ राशन में दाल, शक्कर, केरोसिन का तेल दिया जाए।

भदभदा-कलियासोत डैम के 1-1 गेट खोले गए

- भोपाल में अब तक 51.8 इंच बारिश; सामान्य से 39 प्रतिशत ज्यादा

भोपाल (नप्र)। कैचमेंट एरिया में बारिश होने से भोपाल के भदभदा और कलियासोत डैम के 1-1 गेट सोमवार सुबह खोल दिए गए। सुबह साढ़े 9 बजे भदभदा डैम का एक गेट खोला गया। फिर कलियासोत डैम का गेट खुला। केरवा डैम के गेट से भी पानी छलक रहा है। यहां 8 ऑटोमैटिक गेट हैं। भदभदा डैम का सीजन में 10वीं बार गेट खुला है। वहीं, कलियासोत डैम के 14 बार गेट खोले जा चुके हैं। भोपाल के पास कोलार डैम भी पानी का लेवल फुल टैंक लेवल पर पहुंच गया है। केरवा भी फुल हो चुका है।

आखिरी सप्ताह में ऐसा रहता है मौसम

मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के आखिरी सप्ताह में गर्मी का असर बढ़ जाता है, क्योंकि मानसून की विदाई होने लगती है। इस वजह से तापमान 33-34 डिग्री के पार पहुंच जाता है। यही कारण है कि पिछले 4 साल की तुलना में इस बार गर्मी का असर भी ज्यादा है। इस बार भी ऐसा ही मौसम है। दिन में उमस और गर्मी का असर है। पिछले कुछ दिन से शाम को हल्की बारिश का दौर चल रहा है।

अबकी बार सामान्य से ज्यादा बारिश

बता दें कि इस मानसून भोपाल में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भोपाल की सामान्य बारिश 37.6 इंच है, जबकि इस बार 50.8 इंच पानी गिर गया है। यानी, 39 प्रतिशत बारिश ज्यादा हो चुकी है।

'सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाएं मंदिर'

विश्व हिन्दू परिषद ने संतों के साथ किया प्रदर्शन, तिरुपति प्रसाद में मिलावट करने वालों को फांसी की मांग

भोपाल (नप्र)। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल की मिलावट को लेकर शुरु हुआ विवाद का अब मप्र में भी असर पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में राजभवन के करीब पीपल चौराहे पर विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने संतों के साथ प्रदर्शन किया। विहिप कार्यकर्ताओं और संतों ने मप्र के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। प्रदर्शन में विहिप के प्रांत मंत्री राजेश जैन, अनिलानंद महाराज, साध्वी सीमानाथ योगी, महंत पुरुषोत्तमानंद, महंत कहैन्यादास, महंत लोकनाथ योगी, महंत राधामोहन दास, महंत महामंडलेश्वर राम भूषण दास, महंत देवगिरी, महंत वैष्णव सरकार, मनोज बांगा सकल जैन समाज अध्यक्ष, बलाई समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश हिर्वे, विहिप प्रांत अध्यक्ष केएल शर्मा मौजूद थे।

तिरुपति मंदिर प्रसाद में मिलावट हिन्दू आस्था पर चोटः विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत मंत्री राजेश जैन ने कहा- हिन्दुओं की आस्थाओं, मान्यताओं पर प्रहार हो रहे हैं। तिरुपति के प्रसाद में मछली का तेल और बीफ ये बहुत बड़ा विषय है हिन्दुओं की आस्थाओं के साथ ये खिलवाड़ है। हर हिन्दू जो प्रसाद ग्रहण करता है उसमें इस तरह की मिलावट करके हमारा धर्म भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया गया है। हम सरकार से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। कोई भी दोषी ना बचे। ऐसे दोषियों को फांसी दे देनी चाहिए। नहीं तो समाज के सुपुर्द कर देना चाहिए। समाज उनका निर्णय कर सकता है।

सरकारी नियंत्रण से मुक्त हों मंदिरः राजेश जैन ने कहा- जितने भी मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं उन सबको सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। हिन्दू समाज अपने मंदिरों की रक्षा करने में सक्षम है। पहले मुगल आक्रांताओं ने मंदिरों को लूटा और अंग्रेजों ने उनका सरकारी करण किया। ये लूट 77 साल से चल रही है। वो लूट आगे नहीं चल पाएगी। ये हिन्दू समाज का संकल्प है। हम समाज को जगाएंगे। और सभी मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में हैं वो नियंत्रण समाज के हाथ में लाएंगे।

धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं को दी गई दान की राशिः राजेश जैन ने कहा- कई बार तो हिंदुओं के धर्म पर आघात कर हिंदुओं का धर्मांतरण करने वाली संस्थाओं को इस पवित्र राशि से अनुदान देने की बातें भी सामने आई हैं। कई अन्य राज्य सरकारें भी मंदिरों की संपत्ति व आय का लगातार दुरुपयोग करती रहती हैं और उनका उपयोग हिंदू विरोधी कामों में करती रही है। हमारे देश में संविधान के सर्वोपरि होने की दुहाई बार-बार दी जाती है। लेकिन, दुर्भाग्य से हिंदुओं की आस्थाओं के केंद्र मंदिरों पर विभिन्न सरकारें अपना नियंत्रण कर हिंदुओं की भावनाओं के साथ सबसे धोखाधड़ी संविधान की आड़ में ही कर रही हैं। जो सरकारें संविधान की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं वे ही संविधान की आत्मा की धज्जियां उड़ा रही है।

अपने स्वार्थ के कारण मंदिरों का अधिग्रहण कर सरकारें संविधान की धारा 12,25 व 26 का खुला उल्लंघन कर रही हैं। क्या देश की आजादी के 77 साल बाद भी हिंदुओं को अपने मंदिरों का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती? अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक संस्थान चलाने की अनुमति है लेकिन, हिंदू को यह संविधान सम्मत अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा?

विवाह पूर्व कुंडली मिलान से ज्यादा जरूरी है सिकल सेल कार्ड का मिलान : राज्यपाल

कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय छात्रावास में हुआ स्क्रीनिंग शिविर

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि स्वस्थ पीढ़ी के लिए विवाह पूर्व जन्म कुंडली मिलान से ज्यादा जरूरी सिकल सेल जेनेटिक काऊंसलिंग कार्ड का मिलान करना है, क्योंकि यदि सिकल सेल रोगी और वाहक आपस में विवाह करते हैं, तो निश्चित ही उनकी सन्तान सिकल सेल रोग से ग्रसित होगी। यदि पति-पत्नी दोनों इस रोग के वाहक हैं, तो भी उनकी भावी सन्तान सिकल सेल से प्रभावित होगी, इसकी ज्यादा संभावना रहती है। राज्यपाल श्री पटेल ने सिकल सेल एनीमिया रोगियों को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखने और अपने घर का पका भोजन ही करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति अपनी दिनचर्या में नियमित पौष्टिक आहार, योग और व्यायाम को शामिल करें। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में आयोजित सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग शिविर को संबोधित कर रहे थे। जनजातीय कार्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस स्क्रीनिंग शिविर में जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह भी उपस्थित थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भधारण

के पूर्व और गर्भावस्था में भी मेडिकल काऊंसलिंग बहुत जरूरी है। अब जन्म के 72 घंटों में सिकल सेल का पता लगने पर नवजात शिशुओं के विशेष उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास कर रही हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने संबंधित विभागों को सिकल सेल स्क्रीनिंग के लिए लक्षित प्रत्येक व्यक्ति की अत्यंत गंभीरता से स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिए।

सिकल सेल जागरूकता के लिए बेटियाँ आगे आयें

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृ-शक्ति का विशेष महत्व है। सिकल सेल उन्मूलन के लिए बेटियों का योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जागरूकता के लिए बेटियां आगे आयें और अपने करीबियों, रिश्तेदारों व आस-पड़ौस के लोगों को इस रोग के बारे में बताएं और रक्त की जांच कराने को कहें। राज्यपाल श्री पटेल ने उपस्थित जनों से अपील की कि सिकल सेल रोग के लक्षण, रोकथाम और उन्मूलन के प्रयासों में हर व्यक्ति सक्रिय योगदान करे। मानवता की सेवा के इस पुनीत कार्य के प्रति हमेशा संवेदनशील रहें। उन्होंने 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त बनाने के संकल्प के लिए सामूहिक सहभागिता का आहवान किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलन और जनजातीय वीर नायकों के छायाचित्रों पर माल्यार्पण के साथ किया। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह और कन्या महाविद्यालय छात्रावास की बालिकाओं ने राज्यपाल श्री पटेल का पुष्प-गुच्छ भेंट कर आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री पटेल ने कन्या महाविद्यालय छात्रावास की छात्राओं को उपहार भी दिये।

व्यवस्था करेंगे कि हर छात्रावास में एक नर्स हर महीने विद्यार्थियों की जांच करें- जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के सिकल सेल उन्मूलन मिशन में राज्यपाल श्री पटेल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने जनजातीय हितों के लिए राज्यपाल श्री पटेल के मार्गदर्शन में राजभवन में स्थापित किए गए 'जनजातीय प्रकोष्ठ' की मुक्त-कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल श्री पटेल जनजातीय वर्ग के प्रति अत्यंत ही संवेदनशील हैं। श्री पटेल के प्रयासों से ही प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का कार्य मिशन मोड पर तेजी से जारी है।

सांस्कृतिक पत्रिका 'रंग संवाद' को इंडियन फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार

भोपाल। संस्कृति के विविध आयामों को समेटती कलात्मक पत्रिका 'रंग संवाद' को एक बार फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स नई दिल्ली ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केन्द्र आरएनटीयू के लिए वरिष्ठ कला समीक्षक विनय उपाध्याय विगत डेढ़ दशक से 'रंग संवाद' का सम्पादन कर रहे हैं। आईसेक्ट पब्लिकेशन समूह की इस लोकप्रिय पत्रिका का प्रसार भारत सहित 35 से भी अधिक देशों में है। प्रधान संपादक संतोष चौबे हिन्दी में सांस्कृतिक पत्रकारिता को रचनात्मक गति देने तथा सुरूचि का परिवेश निर्मित करने में 'रंग संवाद' की भूमिका को अहम मानते हैं। आईसेक्ट पब्लिकेशन के वरिष्ठ प्रबंधक महीप निगम ने बताया कि श्रेष्ठ संपादन और प्रकाशन की श्रेणी में 'रंग संवाद' का लगातार तीसरे वर्ष निर्णायक ज्यूरी द्वारा पुरस्कार के लिए चयन किया है। इस पत्रिका के सहायक संपादक मुदित श्रीवास्तव तथा तकनीकी समन्वयक अमीन उद्दीन शेख हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने झारखण्ड में बाबा बैद्यनाथ महादेव मंदिर में की पूजा-अर्चना

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सोमवार को झारखण्ड प्रवास के दौरान देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग श्री बाबा बैद्यनाथ धाम में देवादिदेव भगवान महादेव के दर्शन कर पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देश व प्रदेशवासियों के मंगल और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान से प्रार्थना की कि आपकी कृपा सभी पर अनवरत बरसती रहे।